● जयपुर, गुरुवार 14 नवंबर 24● वर्ष 14● अंक 87● पृष्ठ : 8● मूल्य : 1 रुपये
www.chamaktarajasthan.in | Email : chamaktarajasthan8789@gmail.com

डाक पंजीयन संख्या: RJ/JPC/D19/2024-25
RNI. No. RAJHIND/2011/40950

दैनिक
राज्य तथा केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त
सच के साथ मजबूती से बढ़ाये क़दम

चमकता राजस्थान

विज्ञापन के लिए : 93145 05000
जयपुर से प्रकाशित एवं प्रसारित
अजमेर, सीकर, झुंझनुं, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूँदी, धौलपुर, हिंडौन, भरतपुर, झालावाड़, जोधपुर, बीकानेर से प्रसारित

सुविचार

"सत्य को हज़ार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा।"
● स्वामी विवेकानंद

पेज @3 जेडीए द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस जविप्रा कैलाश चन्द विश्नोई के उचित ...

पेज @4 पूर्णिमा महास्नान के साथ 15 को होगा विश्व प्रसिद्ध पुष्कर...

पेज @8 जोन 10 में जेडीए खसरें की बेशकीमती सरकारी ज़मीन पर 'अशोक विहार...

'बुलडोजर एक्शन' पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

आरोपित या दोषी का घर ध्वस्त नहीं किया जा सकता

एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपित या दोषी के घर को ध्वस्त कर दिया जाता है तो उसका परिवार मुआवजे का हकदार होगा। साथ ही मनमाने ढंग से या अवैध तरीके से काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर किसी आरोपित की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय नहीं ले सकती। न्याय करने का काम न्यायपालिका का है। कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि किसी का घर उसकी उम्मीदें है। हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी न छिने और हर एक का सपना होता है कि उसके पास आश्रय हो।

- कानून का पालन किए बगैर ध्वस्तीकरण पर परिवार होगा मुआवजे का हकदार
- अवैध तरीके से काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी

कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप हो। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हम आदेश जारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के कई फैसले पर भी विचार किया है। कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखे और राज्य में कानून का ही राज होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमने शक्तियों के पृथक्करण के साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान दिया है कि कार्यकारी और न्यायिक वर्ग अपने संबंधित क्षेत्रों में कैसे काम करे।

कोर्ट ने कहा- संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर किया विचार

कोर्ट ने कहा कि हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है जो व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि व्यक्तियों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि क्या अपराध करने वाले आरोपित या दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संपत्ति को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिराया जा सकता है। हमने आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता के मुद्दों पर विचार किया है और आरोपित के मामले में पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। यह मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया में अभियुक्तों के अपराध का पहले से आकलन नहीं किया जाना चाहिए कि वह अपराधी है।

झारखंड: पहले चरण की 43 सीटों पर 64.86 मतदान

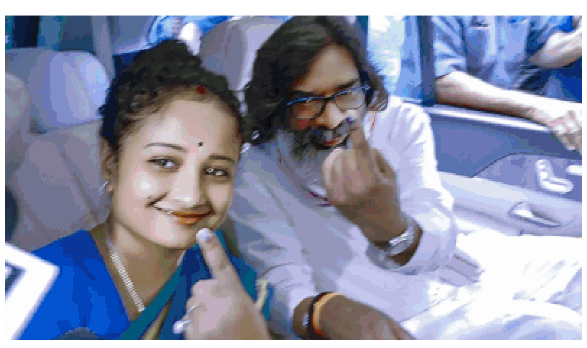

रांची/एजेंसी।

झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के तहत 43 सीटों पर बुधवार को मतदान संपन्न हो गया। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार कुल 64.86 फीसदी मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यह शाम पांच बजे तक का प्रारंभिक आंकड़ा है। फाइनल आंकड़े में कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। खास बात यह रही कि दशकों तक नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में बंपर वोटिंग हुई। प्रायः सभी बूथों में महिला और युवा मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार सरायकेला-खरसावां जिले की सीटों पर सबसे अधिक 72.19 फीसदी मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम वोटिंग हजारीबाग जिले की सीटों में 59.13 फीसदी दर्ज की गई है। विधानसभावार मतदान प्रतिशत पर निगाह डालें तो कोल्हान प्रमंडल की खरसावां सीट पर सबसे ज्यादा 77.32 प्रतिशत वोट पड़े हैं। रांची शहरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 51.50 मतदाताओं ने ही मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जिन अन्य सीटों पर 70 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है, उसमें बहरागोड़ा में 76.15, लोहरदगा में 73.21, मांडर में 72.13, पोटका में 72.29, सरायकेला में 71.54, सिसई में 71.21 और बिशुनपुर में 70.06 प्रतिशत वोट रिकॉर्ड किया गया है।

इस चरण में 20 सीट अनुसूचित जनजाति और 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि 17 सीट सामान्य हैं। मतदान संपन्न होने के साथ ही कुल 683 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है।

इस चरण के प्रमुख प्रत्याशियों में पूर्व सीएम चंपई सोरेन, उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन, झारखंड सरकार के छह मंत्रियों डॉ. रामेश्वर उरांव, मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुआ, बैद्यनाथ राम और रामदास सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू, पूर्व सीएम अर्जुन अध्यक्ष सीपी सिंह, पूर्व मंत्री सरयू राय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे पूर्व आईपीएस डॉ. अजय कुमार, राज्यसभा की सांसद डॉ. महुआ माजी, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, डॉ नीरा यादव आदि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने मतदाताओं का जताया आभार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दावा, सातों सीटों पर जीतेगी भाजपा

विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी टीम, पार्टी पदाधिकारियों व प्रभारियों से मतदान का पल-पल लेते रहे फीडबैक

चमकता राजस्थान

जयपुर, 13 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया है कि राजस्थान की सातों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। शर्मा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस क्षेत्र में भी गए, वहां की जनता का अपार जन समर्थन भाजपा के प्रति दिखा। उन्होंने कहा कि चुनाव में लगे भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की और जनता ने 11 महीने की सरकार में हुए जनकल्याण के कार्यों के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। राजस्थान की जनता में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता सर्वाधिक है और इसका फायदा इन चुनावों में भाजपा को मिला है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम को मतदान के लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने लोकतंत्र की मजबूती एवं विकास के लिए जागरूकता से मतदान कर अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। राजस्थान की जनता समझदार है और उसने सोच-समझकर मतदान किया है। जनता को पता है कि उसका विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। इसलिए उनका वोट डबल इंजन की सरकार को और मजबूत बनाने के लिए पड़ा है। इस चुनाव में महिला, युवा, किसान, गरीब सहित हर वर्ग का समर्थन भाजपा के साथ था। भाजपा की सभाओं में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ने इसको साबित भी किया। चौरासी की सभा तो ऐतिहासिक थी, जिसमें आदिवासी भाईयों ने हजारों की संख्या में आकर भाजपा के पक्ष में खड़े होकर विभाजनकारी एजेंडे को करारा जवाब दिया।

दिनभर चुनाव मैनेजमेंट टीम और वॉररूम को भी दिए निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे दिन मतदान पर नजर रखी। उन्होंने उपचुनाव वाली सीटों सलूम्बर, चौरासी, झुंझुनूं, खींवसर, दौसा, रामगढ़ एवं देवली-उनियारा में जिम्मेदारी निभा रही चुनावी टीमों, पार्टी पदाधिकारियों व प्रभारियों से मतदान का पल-पल फीडबैक लिया। उन्होंने प्रदेश स्तर पर चुनाव मैनेजमेंट टीम और वॉररूम को टीम को भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कड़ी मेहनत करने वाले समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान सभी सीटों पर दो-दो बार चुनावी सभाएं की। इन चुनावी सभाओं में उमड़े जन सैलाब ने यह तय कर दिया था कि जनता इन चुनावों में भाजपा के साथ है और परिवारवाद, भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस एवं उनके सहयोगियों को सबक सिखाने का मन बना चुकी है।

मथुरा में रिफाइनरी में धमाका, 10 लोग घायल

मथुरा/एजेंसी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया है। यहां रिफाइनरी में ब्लास्ट हो गया, जिसकी आवाज करीब एक किमी दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद आग लगने से करीब 10 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार रात करीब आठ बजे शटडाउन फाइनल के बाद प्लांट शुरू करने के दौरान यह हादसा हुआ। एबीयू प्लांट में फर्नेस फटने से धमाके के साथ आग लग गई।

महाकुंभ 2025 : भारत के जवानों संग इजरायल, अमेरिका और फ्रांस के दिग्गज करेंगे गंगा आरती

प्रयागराज/एजेंसी।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ की नव्यता, दिव्यता और भव्यता का अहसास कराने की तैयारी में जुटी है। वहीं दुनिया के विशिष्ट लोग भी महाकुंभ में सम्मिलित होने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए लालायित हैं। महाकुंभ के दौरान पहली बार इजरायल, अमेरिका और फ्रांस समेत तमाम देशों के दिग्गज गंगा आरती में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ सेना के जवान भी शामिल होंगे।

तटीय सुरक्षा | समुद्र तट की सुरक्षा को लेकर 'सी विजिल' अभ्यास 20-21 नवंबर को

11,098 किमी लंबे समुद्र तट की सुरक्षा परखेगी नौसेना

एजेंसी

नई दिल्ली। देश के 11,098 किमी लंबे समुद्र तट की सुरक्षा परखने के लिए भारतीय नौसेना 20 एवं 21 नवंबर को तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल' करेगी। पश्चिमी नौसेना कमान के अधीन यह अभ्यास गुजरात, दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में एक साथ होगा। इसमें तटीय रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियां भाग लेंगी। साथ ही राज्य समुद्री पुलिस, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क, मत्स्य पालन आदि के कर्मी भी होंगे।

नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि 'पैन-इंडिया' तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल' का चौथा संस्करण अभूतपूर्व पैमाने पर होगा, जिसमें 06 मंत्रालय और 21 संगठन/एजेंसियां शामिल होंगी। अभ्यास का तटीय रक्षा एवं सुरक्षा तत्परता मूल्यांकन चरण 24 अक्टूबर के अंत से सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सहित) में संचालित किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण तटीय रक्षा और सुरक्षा बुनियादी ढांचे का गहन ऑडिट किया जा रहा है।

समुद्री सुरक्षा के बारे में जागरुकता बढ़ाना उद्देश्य

दरअसल, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद तटीय रक्षा को मजबूत करने के लिए अपनाए गए उपायों को बढ़ाने के लिए 2018 में 'सी विजिल' को डिजाइन किया गया था। पूरे 11,098 किलोमीटर लंबे समुद्र तट और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल आर्थिक क्षेत्र को शामिल करते हुए यह व्यापक अभ्यास तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे और मछली पकड़ने वाले समुदाय और तटीय आबादी सहित सभी समुद्री हितधारकों को एक साथ शामिल करेगा। इस अभ्यास का एक उद्देश्य तटीय समुदायों के बीच समुद्री सुरक्षा के बारे में जागरुकता बढ़ाना है। एनसीसी और भारत स्काउट्स और गाइड्स की भागीदारी से मछुआरा समुदायों और तटीय आबादी के उत्साह में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि तटीय सुरक्षा अभ्यास अलग-अलग तटीय राज्यों और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, लेकिन भारतीय नौसेना का अभ्यास 'सी विजिल' राष्ट्रीय स्तर की पहल है, जिसमें भारत की समुद्री रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं का समग्र मूल्यांकन किया जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारी भी पहली बार भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाली सीडीएसआरई टीमों का हिस्सा होंगे। साथ ही राज्य समुद्री पुलिस, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क, मत्स्य पालन आदि के कर्मी भी होंगे।

इस अभ्यास में तटीय संपत्तियों जैसे बंदरगाहों, तेल रिगों, सिंगल पॉइंट मूरिंग्स, केबल लैंडिंग पॉइंट्स और तटीय आबादी सहित महत्वपूर्ण तटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष भारतीय सेना और वायु सेना की भागीदारी और बड़ी संख्या में जहाजों और विमानों की तैनाती ने अभ्यास की गति को बढ़ा दिया है।

भारत-सऊदी साझेदारी प्रगति पर आधारित और भविष्य पर केंद्रित है : डॉ. एस जयशंकर

एजेंसी

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बुधवार को सऊदी अरब के अपने समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ दूसरी भारत-सऊदी अरब सामरिक साझेदारी परिषद की राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी साझेदारी प्रगति पर आधारित और भविष्य पर केंद्रित है। विदेश मंत्री ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि सऊदी अरब का विजन 2030 और विकसित भारत 2047 हमारे उद्योगों के लिए नई साझेदारियां बनाने के लिए पूरक हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय को 26 लाख आबादी के कल्याण और उनकी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सुरक्षा सहयोग भी लगातार बढ़ा है। हम आतंकवाद, उग्रवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में सहयोग कर रहे हैं।

विदेश मंत्री ने एक्स पर कहा कि बैठक में रक्षा भागीदारी, सुरक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, संस्कृति, पर्यटन और युवा आदान-प्रदान तथा हमारे लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित हमारे बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर संयुक्त प्रयासों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

जम्मू-कश्मीर में फिर अनुच्छेद 370 का राग

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश की नई सरकार ने पुराने एजेंडे पर काम करना प्रारम्भ कर दिया है। इससे निश्चित ही यह संकेत मिलता है कि जिस अनुच्छेद 370 और 35ए के कारण कश्मीर को शेष भारत से अलग दिखने जैसी स्थिति थी, वैसी ही स्थिति पैदा करने का प्रयास नई सरकार यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। राज्य की नई सरकार का यह कदम पाकिस्तान के हौसले बढ़ाने वाला लगता है, क्योंकि पाकिस्तान अनुच्छेद 370 के कारण ही कश्मीर को अपना बताने का कुचक्र रचता रहा है।

अनुच्छेद 370 के बहाने राज्य को मिले विशेष अधिकारों के चलते ही पाकिस्तान ने अपना नेटवर्क स्थापित किया था, जिसके कारण वहां के नागरिक भारतीय सेना के प्रति अलगाव का व्यवहार करते दिखाई दिए। उस समय पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर में युवाओं को भ्रमित करते रहते थे। अब उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली प्रदेश की नई सरकार ने जम्मू-कश्मीर में फिर से अलगाव के बीज रोपित करने का काम किया है। जिसमें कांग्रेस की भी भागीदारी है। हालांकि कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। जम्मू-कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 कायम था, तब राज्य ने क्या खोया था, यह पूरा देश जानता है। घाटी में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी घटनाएं होती रहती थी। वर्तमान केंद्र सरकार ने इसे हटाकर कश्मीर को शेष भारत से समरस करने का काम किया है। इसीलिए आज जम्मू-कश्मीर आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगा पाने में बहुत हद तक सफल हुआ है।

वर्तमान में पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के स्वर मुखरित होने लगे हैं। समान नागरिक ×कानून निश्चित ही सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का हिमायती है, लेकिन दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान को मान्यता देने वाले अनुच्छेद 370 को लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह जम्मू-कश्मीर को अलग पहचान देने का काम करता है। इसके चलते कश्मीर का संविधान और ध्वज अलग हो जाएगा, जो भारत के संविधान और तिरंगा से अलग होगा। यह स्थिति डॉ. भीमराव अम्बेडकर के संविधान से अलग प्रकार की होगी। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वह बयान स्वतः ×खारिज हो जाता है, जिसमें वह कहते हैं कि भाजपा संविधान फाड़कर फेंकना चाहती है। इसका एक आशय यह भी है कि कांग्रेस संविधान को बचाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस कौन से संविधान को बचाना चाहती है, यह और स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी जम्मू-कश्मीर को अलग दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने संविधान में इसको जोड़ने से इनकार कर दिया था। अम्बेडकर जी के मना करने के बाद शेख अब्दुल्ला, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की भावना को दरकिनार कर शेख अब्दुल्ला को प्रसन्न करते हुए अनुच्छेद 370 का समावेश संविधान में करा दिया। आज कांग्रेस भले इस बात का दम्भ भरे कि वह संविधान को बचाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के कार्य ऐसे लगते नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की सरकार ने ही आपातकाल लगाकर भारत के नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए थे। उस समय आपातकाल लगाने जैसी स्थिति नहीं थी लेकिन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश पर इसे थोपा गया।आपातकाल संविधान की हत्या जैसा ही कृत्य था।

पांच वर्ष पूर्व केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को विलोपित कर दिया। भाजपा का यह कदम किसी भी प्रकार से किसी के विरोध में इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाजपा के हर घोषणा पत्र में इसे हटाने की बात कही गई। इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए भाजपा को समर्थन मिला। जब जनता ने भाजपा के वादों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया, तब स्वाभाविक रूप से यही कहा जा सकता है कि भाजपा ने वही काम किया, जो जनता चाहती थी। अब जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान चलता है, राज्य का अपना कोई संविधान नहीं है। इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए उसके संवैधानिक अधिकार सीमित हैं। जम्मू-कश्मीर की सरकार संविधान में बदलाव करने का कोई संवैधानिक हक नहीं रखती। यह केंद्र सरकार का काम है। राज्य कोई विधेयक पारित तो कर सकता है, लेकिन वह विधेयक तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक केंद्र की सरकार न चाहे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राज्य की नवगठित सरकार का यह कदम केवल राजनीतिक लाभ के लिए है।

देश में कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने एक साथ आकर इंडी गठबंधन बनाया है। यह गठबंधन बार-बार संविधान बचाने की बात करता रहता है, लेकिन सवाल यह है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने वाले विधेयक पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसे मौन समर्थन भी माना जा सकता है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऐसी कौन-सी राजनीतिक मजबूरी है जो इसकी बहाली के लिए उनको मजबूर कर रही है। क्या इन दलों को यह पता नहीं है कि इन्हीं कानूनों के कारण ही कश्मीर हिन्दू विहीन हो गया है। क्या यह दल फिर से कश्मीर घाटी को उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं। देश में एक समान कानून होना चाहिए, यह सभी चाहते हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर में इसपर मौन हैं। जम्मू-कश्मीर में अगर अनुच्छेद 370 बहाल हो जाता है तो निश्चित ही पाकिस्तान परस्त ताकतें हावी होकर जम्मू-कश्मीर में फिर से अलगाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति न बने, इसलिए कश्मीर में भी देश का संविधान ही लागू रहे, यह समय की मांग है और यह कदम जम्मू-कश्मीर के हित का भी है।

बढ़ते मधुमेह को नियंत्रित करने की वैश्विक चुनौती

ललित गर्ग

डायबिटीज यानी मधुमेह दुनियाभर में तेजी से बढ़ती ऐसी बीमारी है जो अन्य अनेक बीमारियों एवं शरीर की जर्जरता का कारण बनती है, जिसका शिकार हर उम्र के लोगों को देखा जा रहा है। जिन लोगों का शुगर लेवल अक्सर बढ़ा हुआ रहता है उनमें आंखों, किडनी, तंत्रिकाओं, शरीर की सुस्ती और हृदय से संबंधित कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ती इस गंभीर और क्रोनिक बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने, इससे बचाव को लेकर लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि डायबिटीज के मरीज साल-दर साल बढ़ते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनियाभर में 53 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी के शिकार हैं और अगले दो दशकों में रोगियों की संख्या 80 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। विश्व मधुमेह दिवस दुनिया की गंभीरतम बीमारियों में से एक होने की वजह से 160 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है और अपने जागरूकता अभियानों, उपचार तक बेहतर पहुंच की वकालत और मधुमेह से निपटने के लिए गुणवत्तापूर्ण सूचनात्मक सामग्री के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। इस वर्ष, इस दिवस की थीम है 'बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना'। यह थीम लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर मधुमेह के प्रभाव पर प्रकाश डालती है और मधुमेह प्रबंधन-नियंत्रण-जागरूकता के महत्व पर भी जोर देती है और यह बताती है कि इसके लिये संतुलित, योगमय एवं गुणवत्ता जीवन कैसे इस बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। दरअसल, विश्व मधुमेह दिवस को 14 नवंबर को मनाने का मुख्य उद्देश्य सर फ्रेडरिक बैंटिंग को याद करना था। 1992 में सर फ्रेडरिक बैंटिंग ने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह फाउंडेशन (आईडीएफ) के अनुसार, 2021 में मधुमेह के कारण 67 लाख लोगों की मृत्यु हुई और अनुमान है कि उसी वर्ष 53.7 करोड़ (10 में से 1) लोग इस बीमारी के साथ जी रहे थे और अनुमान है कि यह संख्या 2030 में बढ़कर 64.3 करोड़ और 2045 तक 78.3 करोड़ हो जाएगी। यह तथ्य सामने आया है कि मधुमेह से प्रभावित 2 वयस्कों में से 1 यानी 44 प्रतिशत, लगभग 24 करोड़ लोग, अभी तक निदान नहीं करा पाये हैं, उनमें से अधिकांश टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित हैं, जिसे कुछ जीवनशैली में बदलाव, इच्छाशक्ति, योग-साधना और स्वस्थ आहार आदतों से रोका जा सकता है। असंतुलित जीवनशैली के कारण लगभग 54.1 करोड़ वयस्कों को टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का खतरा है। डायबिटीज के होने एवं पनपने के अनेक कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारक फैमिली हिस्ट्री को माना जाता है। यानी कि यदि माता-पिता या भाई-बहन को टाइप-2 डायबिटीज है तो आपको भी मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। अधिक वजन या मोटापा डायबिटीज रोग के लिए एक मुख्य जोखिम है। अध्ययनों से पता चलता है कि मुख्यरूप से पेट पर फैट जमा होने से आपमें डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। अध्ययकर्ताओं ने पाया कि जो लोग अधिक मीठा खाते हैं उनमें पेट की चर्बी बढ़ने का खतरा रहता है। मोटापा से ग्रस्त लोगों में डायबिटीज की स्थिति हृदय रोग और अन्य जटिलताओं को भी बढ़ाने वाली हो सकती है। विशेषज्ञ का मानना है कि शारीरिक निष्क्रियता भी डायबिटीज की जोखिम को बढ़ा देती है। शारीरिक गतिविधि जैसे नियमित रूप से योग-व्यायाम वजन और खेलकूद से वजन को नियंत्रित करने में मदद करती है और इससे ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। मधुमेह से बचे रहने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम जरूर करें। टाइप-2 डायबिटीज होने का जोखिम उन लोगों में अधिक होता है, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान मधुमेह का पता चलता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस अवधि में शुगर के स्तर को कंट्रोल में रखने की सलाह देते हैं। गर्भावधि में मधुमेह के कारण ब्लड शुगर का स्तर बढ़ा रहता है जिसका असर गर्भवती और बच्चे दोनों की सेहत पर देखा जाता है। डॉक्टर बताते हैं, भले ही दुनियाभर में सबसे ज्यादा मरीज टाइप-2 डायबिटीज के देखे जाते रहे हैं पर मधुमेह चार प्रकार का होता है। इसे उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारी समझना या युवावस्था में शुगर की समस्या को अनदेखा करना आपके लिए दिक्कतें बढ़ाने वाला हो सकती है। बढ़े रहने वाले शुगर लेवल का असर हृदय और आंखों की सेहत पर भी पड़ सकता है, इसलिए डायबिटीज को हल्के में लेने की भूल नहीं की जानी चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को अपने खाने पीने के अलावा नींद का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। कम नींद के कारण ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव हो सकता है। भोजन और एक्सरसाइज के अलावा नींद भी शरीर के लिए उतनी ही जरूरी होती है। नींद पूरी न होने से शरीर सुस्त हो जाता है और तनाव भी बढ़ता है। ऐसे में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। शरीर में जब शुगर का लेवल बढ़ता या घटता है तो नींद से जुड़ी समस्याएं होने लगती है। खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को हमेशा पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। यदि आपको देर रात तक जागने की आदत है या फिर आप देर रात तक जागकर काम करते हैं तो आपकी यह आदत आप पर भारी पड़ सकती है। अनियंत्रित मधुमेह हृदय संबंधी समस्याओं, तंत्रिका क्षति, गुर्दे की क्षति, पैर की क्षति, त्वचा संक्रमण, स्तंभन दोष, अवसाद, दंत समस्याओं जैसी घातक जटिलताओं को जन्म दे सकता है। चिकित्सा-विज्ञान की अपूर्व प्रगति के बावजूद मधुमेह जैसी जटिल एवं असाध्य बीमारी का राक्षसी-पंजा नियंत्रण से बाहर है, इसलिये व्यक्ति को खुद को खुद के प्रति जागरूक होना होगा।

मधुमेह का नियंत्रित करने के लिये योग-ध्यान-साधना-प्रातःभ्रमण की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैज्ञानिक डॉ. घियोपोर ने बहुत पहले अपने अनुसंधान में बताया कि ध्यान एवं योग करने वाले व्यक्तियों की साइकोलॉजी में असाधारण रूप से परिवर्तन होता है। ऐसे व्यक्तियों में घबराहट, उत्तेजना, मानसिक तनाव, उग्रता, मनोकायिक बीमारियां, स्वार्थपरता और विकारों में कमी पाई गयी हैं तथा आत्मविश्वास, सहनशक्ति, स्थिरता, कार्यदक्षता, विनोदप्रियता, एकाग्रता आदि गुणों में वृद्धि देखी गयी है। ये ध्यान-साधना एवं योग में प्रत्यक्ष लाभ अनुभूत किये गये हैं। इसीलिये मधुमेह को परास्त करने के लिये इन गुणों युक्त जीवनशैली को अपनाया जाना चाहिए। सम्पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ जीवनरूपी प्रयोगशाला में इसे प्रायोगिक रूप देकर जीवन में मधुमेह रूपी-राक्षस को निस्तेज करके जीवन में आनन्द का अवतरण किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह फाउंडेशन के अनुसार, यह अनुमान है कि लगभग 54.1 करोड़ वयस्कों को टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का खतरा है, जो कि दुनिया भर में सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है, ताकि जागरूकता कार्यक्रमों और गुणवत्ता वाले मधुमेह शैक्षिक प्लेटफार्मों को बढ़ावा देकर इस जोखिम को कम किया जाना चाहिए। हम देखते है कि पुरानी पीढ़ी के लोग जीवन के आठवें या नौवें दशक में भी स्वस्थ एवं स्वावलम्बी है। गांवों की स्थिति भी काफी सुखद है, मधुमेह रोगियों की संख्या वहां शहरों की अपेक्षा काफी कम है। इसका कारण है सहज, प्रकृतिमय और चिन्तामुक्त जीवन, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा-पानी, सात्विक-संतुलित आहार और भरपूर मेहनत। महानगरों की भाग-दौड़ भरी जिन्दगी में आदमी मात्र मशीन बनकर रह गया है। अपने स्वास्थ्य के बारे सोचने एवं समझने का समय भी उसके पास नहीं है। विकास की तीव्र गति से उपजी अति तनावपूर्ण जीवनशैली एवं प्रतिस्पर्धाओं ने चिन्ता एवं तनावों को जन्म दिया है, जो मधुमेह को बढ़ाते हैं। अपेक्षा है आशावादी दृष्टिकोण एवं आहार संयम को अपनाएं। मधुमेह से लड़ने के लिये संकल्प जगाये एवं प्रमाद त्यागे। संतुलित जीवन जीएं। तनावों-दबावों को अपने पर हावी न होने दे। सोचो, जिन्दगी मात्र जीने के लिये नहीं, स्वस्थता एवं सरसता से जीने के लिये हैं।

सत्ता की बंदरबांट के बीच मुफ्तखोरी के एलान

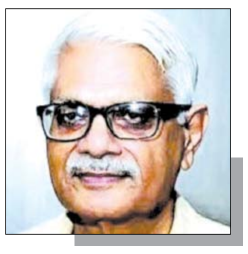

गिरीश्वर मिश्र

विधानसभा या लोकसभा के चुनाव राजनैतिक दलों के आंतरिक स्वभाव को उभार कर सामने लाने में बड़े मददगार होते हैं। दल कोई भी हो सत्ता हासिल करना और सत्तासीन होकर उस पर कब्जा बनाए रखना ही उनका परम धर्म हो चुका है। सत्ता के लिए आर्त पुकार जनता तक पहुँचाने की राजनीति जटिल और बहु आयामी होती जा रही है। चुनावी मौसम आते ही राजनीतिक गहमागहमी तेज हो जाती है। नेताओं की अंतरात्मा जाग उठती है और सत्ता-यात्रा में आने वाले सारे बंधनों और अवरोधों को पार करने को छटपटाने लगती है। सत्ता के लिए वे किसी से कोई भी समझौता करने को व्यग्र दिखते हैं। वे अपना दल छोड़ कर दूसरे धुर विरोधी दल में प्रवेश लेने से नहीं कतराते। आज लगभग सभी दल इस तरह की उठापटक को जायज और स्वाभाविक ठहराते हैं, आख़िर युद्ध में सब कुछ उचित जो ठहरा।

चूँकि यह प्रवृत्ति किसी एक दल की न होकर सभी दलों की होती जा रही है, राजनैतिक हलकों में इसे सामान्य रणनीति का हिस्सा मान लिया जाता है। अब वैचारिक रुझान या किसी आदर्श या मूल्य से जुड़े आधार से ज़्यादातर दल अपना कोई रिश्ता नहीं रखते। सभी दलों के स्वर और रीति-नीति में बहुत अंतर नहीं दिखता। कभी राजा जी, मालवीय जी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य जेबी कृपालानी और डॉ. राममनोहर लोहिया जैसे अनेक राजनेता वैचारिक और नीतिगत असहमति और जन-कल्याण के प्रश्नों पर टकराहट से अपनी मूल पार्टी से अलग हुए थे। अपनी दृष्टि के प्रति उनकी आस्था के पीछे कोई सीमित स्वार्थ नहीं था और वे उसके प्रति

स्वाभाविक रूप से जुड़े थे। शायद वे उस जमाने के थे जब निःस्वार्थ भाव से देश की सेवा और समाज के हित की दृष्टि से प्रेरित हो कर लोग राजनीति की ओर आते थे। इस सिलसिले में बहुतों ने पाने की जगह कुछ खोया गँवाया। राजनीति की दिशा में उनका कदम किसी निजी, पारिवारिक या समुदाय के दबाव से या दबदबा बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि अपनी पसंद से उठाया गया कदम होता था। उनकी नज़र समाज की कमियों और कमज़ोरियों का सामना करने पर रहती थी। ऐसे नेताओं की अच्छी संख्या होती थी जो अपने बलिदान और त्याग के लिए तैयार रहते थे। समाज की सेवा करने को उन्होंने चुना था।

राजनैतिक दलों की अपनी-अपनी वैचारिक पसंद नापसन्द तो होती थी और होनी भी चाहिए पर सबकुछ के बावजूद उन नेताओं के पास देश का एक नक़्शा होता था और बिना किसी संदेह के देशहित ही उनका सबसे महत्वपूर्ण सरोकार होता था। जमीन से उठ कर आने वाले ऐसे प्रामाणिक नेतृत्व की साख उनके द्वारा अर्जित होती थी। वे किसी हाईकमान की कृपा का मुंहताज नहीं होती थी। आज की तरह अपने लिए धनसंग्रह करते रहना उनका उद्देश्य नहीं होता था। उनमें देश-निर्माण का स्वाभाविक जज़्बा और उत्साह होता था जो उनके कार्यों में भी झलकता था। अब स्वतंत्र होने के पचहत्तर साल बीतने के बाद राजनैतिक परिवेश में जोड़-तोड़ की जो प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आ रही हैं वे राजनीति के तेजी से बदलते स्वभाव का संकेत दे रही हैं।

हर चुनाव की सुगबगाहट के साथ राजनैतिक दलों द्वारा रेवड़ी बाँटने की नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। वादों और घोषणाओं की झड़ी लग जा रही है। इसमें क्या कुछ नहीं शामिल होता हैः नौकरी, बिजली, घर, सम्मान निधि, गैस सिलेंडर, कर्जमाफ़ी, सस्ता-कर्ज़, मुफ़्त वाई-फ़ाई, गरीब को वजीफ़े, आरक्षण की सुविधा यानी जो भी मन करे नेता लोग सब कुछ मतदाता को देने की घोषणा करते नहीं अघा रहे है। अब ज़मींदारों के तर्ज़ पर नेताजी मनमज़ी से कोई भी एलान कर सकते हैं। मुफ़्त की सुविधायें देने के पीछे कोई आर्थिक-सामाजिक नीतिगत आधार नहीं होता है। जाति, उपजाति, क्षेत्र और धर्म जैसे आधार में बांध कर चुनाव की तैयारी कस्टमाइज्ड प्रलोभन देने की मुहिम चल रही है। इस तरह की प्रक्रिया का कोई ओर-छोर नहीं दिखाई पड़ता है। सुविधा और धन बाँट-बाँट कर जनता से वोट बटोरने की रीति-राजनीति में जन-भागीदारी को दूषित कर रही है। आज एमएलए और एमपी के चुनाव में करोड़ों के खर्च होते हैं। इसलिए प्रत्याशी भी करोड़पति होते हैं। ऊपर से संदिग्ध अपराधी भी शामिल होते हैं। अब धनबल और बाहुबल के बिना राजनीति की कल्पना कठिन हो रही है। तुष्टिकरण के सहारे राजनीति लम्बी पारी नहीं खेल सकेगी। उल्टे यह देश की जड़ों को खोखला करने वाली युक्ति है। निर्वाचन आयोग, सरकार और राजनैतिक दलों को इसे नियंत्रित करने के लिए कारगर कदम उठाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

देश की आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरेंगे सीजेआई खन्ना!

मनोज कुमार अग्रवाल

आप जानते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने हैं। उन्होंने 11 नवंबर को चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल छह महीने एक दिन का होगा। अगले साल ही 13 मार्च को जस्टिस खन्ना रिटायर हो जा जाएंगे। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा है लेकिन इस बात में लोगों की खास दिलचस्पी है कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल, उनमें संभावना, उनके न्यायिक में फैसले और भारत के न्यायिक तंत्र में निहित सीमाओं के संदर्भ में कैसा रहेगा।

आपको बता दें कि भारत में अल्प कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीशों का यह इतिहास रहा है, कि अगर वो कोशिश करें तो सुधार को ऐसी दिशा तय कर सकते हैं, जिसका अनुसरण उनके बाद आने के वाले जस्टिस भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक गलतियों और खामियों से बचने में सीजेआई की मुख्य भूमिका होती है। प्रशासकीय मुखिया के तौर पर भी और न्यायिक परिवार के चीफ बतौर भी। सिस्टम की सीमाएं कुछ विसंगतियों को अपरिहार्य बना सकती हैं, लेकिन सीजेआई उनके प्रभाव को कम करने और हल्का करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। हालांकि केवल लंबित मुकदमों की संख्या ही अकेला मुद्दा नहीं है, जिससे नए सीजेआई को चिंतित होना चाहिए। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के कॉलेजियम ने जस्टिस खन्ना की नियुक्ति की सिफारिश की थी, तब वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। उस समय 32 अन्य हाई कोर्ट जजों की वरिष्ठता (हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त की तारीख के संदर्भ में) को नजरअंदाज कर जस्टिस कता का नाम आगे बढ़ाया गया था। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कॉलेजियम ने जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश इसलिए की थी क्योंकि विचार करने योग्य दूसरे नामों के मुकाबले जस्टिस खन्ना का सीजेआई बनना उचित है। तथ्य यह है कि कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर किसी नाम को, उसकी योग्यता और ईमानदारी की बजाय उसके संभावित कार्यकाल के अंतराल आधार पर पर सिफारिश करे, यह कुछ अजीब लग सकता है। लेकिन भारत में हाल के समय में कम कार्यकाल वाले कई मुख्य न्यायाधीशों के इतिहास को देखते हुए यह एक अतिरिक्त कारक बन जाता है, खासकर तब जब कई उम्मीदवार आ योग्यता के मानदंड पूरा कर रहे हों। तथ्य ये भी है कि जस्टिस खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट से आते हैं और पिछले 20 सालों से इस हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व में करने वाला कोई जज सीजेआई नहीं बना था। रिटायर्ड जज गोगोई के हवाले से, यह भी उनके पक्ष में गया।

जस्टिस खन्ना को 2005 में एडीशनल हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया और फरवरी 2006 में वो परमानेंट जज बन आ गए। परमानेंट जज बनने से पहले वकालत में उनका अनुभव 23 साल का हो रहा था। इसके अलावा उन्होंने टैक्स मामलों, मध्यस्थता, कंपनी लॉ, भूमि अधिग्रहण, स्वास्थ्य और पर्यावरण से वे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के ट्रिब्यूनल में भी के काम किया। अक्सर सार्वजनिक रूप से बोलने और यह सार्वजनिक कार्यक्रमों में राजनेताओं से साथ दिखने की कामकाजी जरूरतों के बावजूद, उनके सार्वजनिक रिकॉर्ड को देखते हुए, कमोवेश उनकी एकांतप्रिय छवि रही है। हाल के सालों में सीजेआई कार्यालय, मास्टर ऑफ दि रोस्टर की दोहरी भूमिका के चलते लगातार सार्वजनिक पड़ताल के दायरे हुई में आता गया है। मास्टर ऑफ दि रोस्टर के रूप में प्रत्येक सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट में जजों के रोस्टर को निर्धारित करते हैं। हालांकि मुकदमों की उपलब्धता और उनको वरिष्ठता के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा नियमित रूप से रोस्टर के मुताबिक अलग-अलग जजों को आवंटित किया जाता है। लेकिन समय-समय पर मास्टर ऑफ दि रोस्टर मुकदमों की लिस्टिंग में बदलाव करता है। यह अक्सर इस आलोचना को जन्म देता है कि मास्टर ऑफ दि रोस्टर की शक्तियां मनमानी हैं और किसी मामले में सरकार के पक्ष में नतीजे लाने के लिए, मुकदमे की सुनवाई को सुनिश्चित करने में इसके दुरुपयोग की संभावना है। चाहे यह किसी राजनीतिक बंदी की जमानत पर सुनवाई हो या किसी विधायिका या कार्यपालिका के निर्णयों को चुनौती देना कुछ खास मान्यताएं और रुझान रखने वाले कुछ खास जजों के सामने सुनवाई के लिए मुकदमे की लिस्टिंग करने से पक्षपाती नतीजे आने की संभवना होती है और इस कारण यह आलोचना के घेरे में आ जाता है। जस्टिस खन्ना उस फैसले के लेखक थे, जिसमें कहा गया था कि न्यायिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता की जरूरत का विरोधाभासी नहीं है। प्रेक्षकों ने पूछा है कि इसलिए क्या जस्टिस खन्ना वही करेंगे, जो वो कहते हैं और मास्टर ऑफ दि रोस्टर के रूप में अपनी शक्तियों के इस्तेमाल में और सुप्रीम कोर्ट की से कॉलेजियम प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे? सीजेआई की शुरू अध्यक्षता वाला सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम एक दूसरा निकाय है, जिसकी कार्यप्रणाली गोपनीय बनी हुई है, जबकि कई प्रधान न्यायाधीशों ने इसे देश अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिशें कीं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के प्रस्तावों पर सरकार के साथ चल रही रस्साकशी में कॉलेजियम संब को कार्यपालिका के सामने झुकते देखा जाता है। हालांकि कानूनन, कॉलेजियम की सिफारिश अगर दुहराई गई हो तो सरकार के लिए बाध्यकारी जन होती है। क्या जस्टिस खन्ना इस ट्रेंड से कोई बिल्कुल अलग रास्ता अखतियारको करेंगे? चूंकि इस पद पर आने वाले अधिकांश मुख्य न्यायाधीश इसे एक कि प्रशासकीय मुद्दे के रूप में देखना पसंद करते हैं, इसलिए सरकार को न्यायिक रूप से अनुशासित करने की किसी भी कोशिश, सफल होने की संभावना कम ही है क्योंकि इससे कॉलेजियम के प्रस्तावित नामों की नियुक्तियों और ट्रांसफर में देरी होती है। जस्टिस खन्ना ने कुछ ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिससे उनके न्यायिक फलसफे का अंदाजा लगता है, जिसे कई जानकार सम सरकार समर्थक होने के रूप में देख सकते हैं। उन्होंने ईवीएम में डाले गए 100 प्रतिशत बोटों का वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) के साथ मिलान करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस खत्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत दी और बीते जुलाई में इस आधार पर उन्हें नियमित जमानत दी कि वो 90 दिनों तक जेल में रह चुके थे। जमानत देने के बाद अदालत ने मुख्यमंत्री के ईस्ट तौर पर काम करने की उनकी सीमाएं निर्धारित की थीं जिसके बाद उन्होंने कि इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने की से बरकरार रखने पर सहमति दी थी, जिसके तहत तत्कालीन जम्मू और कश्मीर कम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा हासिल था। उन्होंने दलील दी कि विशेष दर्जे को रद्द किया जाना, संघीय ढांचे का बंधन नहीं है क्योंकि जम्मू और कश्मीर प्रति में रहने वाले नागरिकों को वही दर्जा और अधिकार प्राप्त होगा जो देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले नागरिकों को हासिल हैं। उन्होंने अपने साथी जजों चान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल के साथ, सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेने की सहमति दी थी कि वह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के राज्य का दर्जा बहाल करेगी। लद्दाख को नोन केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन अपने अलग फैसले में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के गंभीर परिणाम होते हैं और इसका संघीय ढांचे पर असर होता एक है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने को जायज ठहराने के लिए जो मजबूत और ठोस आधार की जरूरत थी और इसमें संविधान के अनुच्छेद तीन का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या सरकार इन शर्तों को पूरा कर रही थी? वो पांच जजों की उस बेंच का हिस्सा क भी थे, जिसने अपने फैसले में यह कहते हुए केंद्र सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था कि दानदाताओं को निजता का चाल अधिकार नहीं है। वहीं जस्टिस खन्ना विवादों से परे नहीं हैं। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की उस बेंच का वह हिस्सा थे, जिसने सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व कर्मचारी द्वारा गोगोई के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज करने के लिए शनिवार (20 अप्रैल, 2019) को सुनवाई की थी। इस बैंच में जस्टिस गोगोई और जस्टिस अरुण मिश्रा के अलावा जस्टिस खना की मौजूदगी ने प्रेक्षकों को भी हैरानी में डाल दिया था क्योंकि बेंच ने मीडिया को आरोपों की रिपोर्टिंग करने से रोकने का निर्देश दिया था, जबकि इस सुनवाई ने अपने आप में गोगोई के हितों के टकराव को उजागर कर दिया था। हालांकि बेंच के फैसले में गोगोई को बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की आंतरिक जांच में गोगोई को क्लीन चिट दे दी गई और इस रिपोर्ट को गोपनीय रख लिया गया। अपने कार्यकाल के समाप्त होने पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस खना की, उनके उच्च निष्पक्षता और शांत रहने की क्षमता और कोर्ट की गर्मागरम बहसों के बीच मुस्कुराते रहने और साथ ही सीजेआई कार्यालय में समृद्ध अनुभव जोड़ने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की है। व्यक्तिगत रूप से जस्टिस खन्ना को, अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर जजों के परिवार से आने के नाते काफी सम्मान हासिल है। । वह सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हंस राज खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान हैबियस कॉर्पस के मामले में अकेली असहमति जताई थी और कहा था कि बिना उचित प्रक्रिया के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने अगले सीजेआई के चुनाव में उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया था। जस्टिस एचआर खन्ना ने इसके बाद इस्तीफा दे दिया था और अपनी अलग छवि पेश कर एक मिसाल कायम की थी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

जयपुर विकास प्राधिकरण कर रहा जमीनी स्तर पर जीरो टॉलरेंस निति को चरितार्थ

जेडीए द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस जविप्रा कैलाश चन्द विश्नोई के उचित दिशा-निर्देश में दिया गया प्रभावी कार्रवाई को अंजाम

जेडीए ने तीस बीघा भूमि पर छः अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त , अन्य स्थानों से हटाए अतिक्रमण

चमकता राजस्थान

जयपुर, (खलील कुरैशी) 13 नवम्बर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-12 में निजी खातेदारी करीब 30 बीघा कृषि भूमि पर 06 नवीन अवैध कॉलोनियों का प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जोन-4 में सरस्वती नगर भूखण्ड संख्या-03 के पास सवाई गैटोर में सरकारी आम रास्तें को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया कि जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सिरसी, जिला जयपुर में करीब 07 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ''राजविहार-प्रथम'' के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गांव सिरसी, जिला जयपुर में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ''राजविहार-द्वितीय'' के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, प्लाटों की बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गांव सिरसी जिला जयपुर में ही करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ''राजविहार-तृतीय'' के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गांव सिरसी जिला जयपुर में ही खसरा नं. 513 करीब 06 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। इसी प्रकार जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गांव सिरसी, में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ''हनुमान वाटिका'' के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात निर्माणाधीन 03 अवैध विला का निर्माण, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गांव सिवार, जिला जयपुर में करीब 07 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ''शिवांचल विहार'' के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें,प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-04, 12 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। साथ ही जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सरस्वती नगर भूखण्ड संख्या-03 के पास सवाई गैटोर में आम रास्तें पर अवैध दीवार बनाकर कब्जा-अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध किया गया था जिससे स्थानीय लोगों आमजन को रास्तें को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर जोन-04 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित मदर टैरेसा कॉलोनी में आवासीय भूखण्ड संख्या-25 में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अवैध रूप से टीनषेड का स्ट्रेक्चर खडाकर कबाड़ का गोदाम बनाकर व्यावसायिक गतिविधि का संचालन किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर जोन-04 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया।

संक्षिप्त समाचार

बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय में स्वरोजगार व कौशल उन्नयन कार्यक्रम का हुआ आयोजन

- प्रोफ़ेसर नरेश कुमार मीणा के निर्देशन में तीन दिवसीय सौंदर्यीकरण प्रक्षिशण

चमकता राजस्थान। शाहपुरा (खलील कुरैशी) शाहपुरा शहर स्थित बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय में स्वरोजगार व कौशल उन्नयन हेतु प्राचार्य प्रो. नरेश कुमार मीना के निर्देशन में महिला प्रकोष्ठ के अन्तर्गत तीन दिवसीय सौंदर्यीकरण प्रशिक्षण की शुरूआत हुई। प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 व 16 नवम्बर को भी आयोजित होगामहाविद्यालय की विभिन्न संकाय की छात्राओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में छात्राओं को थ्रेडिंग, ब्लीच व फेसियल का प्रशिक्षण दिया गया। एक छात्रा पर ब्लीच व फेसियल करके छात्रा को इसकी बारीकियों को समझाया गया तथा इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के टिप्स भी दिये गये। छात्राओं ने प्रशिक्षण में रूचिपूर्वक भाग लिया तथा विभिन्न प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ प्रभारी सुश्री ज्योत्स्ना, प्रो. अन्जू अग्रवाल, डॉ.नन्दिनी शर्मा, डॉ. लतिका एम.पाण्डे, डॉ. पुष्पा अग्रवाल, डॉ. स्वाति शर्मा, डॉ किरण देशवाल, डॉ. पूजा आर्या उपस्थित रहे । प्रशिक्षण बणी ठणी ब्यूटी पार्लर शाहपुरा की संचालिका ममता शर्मा द्वारा दिया गया।

डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने राजस्व अधिकारियों को जारी किये दिशा निर्देश

रास्ता खोलो अभियान से गांवों, खेतों और ढाणियों की राह होगी आसान

जिला कलक्टर के निर्देश पर 15 नवंबर से होगा 'रास्ता खोलो अभियान' का आगाज

चमकता राजस्थान

- **पुलिस और प्रशासन के सहयोग से हर सप्ताह खुलवाए जाएंगे कम से कम तीन रास्ते**
- **आपसी समझाइश, सहयोग और समन्वय से रास्ते खोलना होगा प्राथमिकता**

जयपुर! (खलील कुरैशी) 13 नवंबर। जिला किसानों के लिए गांव-ढाणी और खेतों की ओर जाने वाली राह आसान करने के लिए जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने नवाचार करते हुए 'रास्ता खोलो अभियान' शुरू करने की कार्ययोजना लागू कर दी है। जिला प्रशासन के इस अभियान से निश्चित रूप से आमजन को राहत मिलेगी ।ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्राप्त हो रहे हैं। रास्तों को लेकर न्यायालय में भी वाद दायर किए जाते रहते हैं। ऐसे प्रकरणों में निरन्तर बढ़ोतरी होने से आमजन को न्यायालय के चक्कर लगाने एवं जन-धन की हानि होने के साथ-साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए प्रशासन ने रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए 'रास्ता खोलो अभियान' चलाने का निर्णय लिया है ।उन्होंने बताया कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे, उपखण्ड अधिकारी सप्ताह में एक बार तहसीलदार, थानाधिकारी, विकास अधिकारी के साथ रास्तों से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे तथा खोले जाने वाले रास्तों का चिन्हीकरण कर सप्ताह में कम से कम तीन रास्तों की समस्या का समाधान करेंगे। बंद रास्ते खुलवाए जाने के पश्चात खंड विकास अधिकारी संबन्धित खोले गए रास्तों पर ग्रेवेल/सी. सी. रोड़ बनवाया जाना सुनिश्चित करेंगें ताकि फिर से कोई रास्ते पर अतिक्रमण नहीं कर पाए। रास्ता खोलो अभियान के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने, रास्ता खुलवाने हेतु राजस्व अधिकारियों, पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जायेगी। यदि किन्हीं कारणों से शुक्रवार को कार्यवाही संभव नहीं हो तो शनिवार अथवा आगामी कार्य दिवस को अनिवार्य रूप से की जाएगी ।रास्ता खोलो अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए समग्र रूप से अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) नोडल अधिकारी रहेंगे एवं अति. जिला कलक्टर (चतुर्थ) सह-नोडल अधिकारी रहेंगें। वहीं, सभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी अपने अपने आवंटित क्षेत्र में प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे एवं संबंधित उपखंड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी रहेंगे।रास्ता खोलो अभियान के तहत आम रास्तों, गोचर भूमि पर अतिक्रमण को हटाने, बंद किए जा चुके खातेदारी रास्तों को खुलवाने, राजस्व अभिलेख में दर्ज रास्ते, काश्तकारों की कृषि जोत के विभाजन करने से पूर्व रास्तों का प्रावधान करने, रास्ते निकालने, राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, राजकीय भूमि पर से सार्वजनिक रास्ता निकालने तथा खातेदार किसान को उसकी जोत यानी खेत तक पहुंचने के लिए राजकीय चारागाह भूमि में से होकर रास्ता देने तथा खातेदारी भूमि में से होकर नवीन रास्ते निकालने और विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

वरिष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉ. सचिन गुप्ता ने शुरू किया अपना ई-पोर्टल, दूरदराज के मरीजों को देंगे परामर्श

आमजन को आसानी से सुलभ होगा चिकित्सा परामर्श एवं स्वास्थ्य लाभ : डॉ. सचिन गुप्ता

चमकता राजस्थान

जयपुरः (खलील कुरैशी) नव इम्पीरियल हॉस्पिटल के वरिष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉ. सचिन गुप्ता ने अपने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नया ई-पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले मरीज और वे लोग, जो किसी कारणवश क्लिनिक नहीं आ सकते, आसानी से परामर्श प्राप्त कर सकेंगेहालांकि, पहले से कई हेल्थ ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन ऑनलाइन ठगी और सुरक्षा के मद्देनजर डॉ. गुप्ता ने यह पोर्टल तैयार करवाया है, जिसमें सुरक्षा और प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा गया है। इस पोर्टल के माध्यम से वे जॉइंट रिप्लेसमेंट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर डॉ सचिन गुप्ता एवं उनकी विशेषज्ञ टीम परामर्श देंगे और मरीजों को उनके घर बैठे ही इलाज की सही दिशा प्रदान करेंगे।

गुरुवार को पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होंगे अटल जन सेवा शिविर

चमकता राजस्थान

- **प्रतिमाह दूसरे गुरुवार को अटल जन सेवा शिविरों का होगा आयोजन**
- **प्रातः 10 बजे से अधिकारी करेंगे आमजन के परिवेदनाओं की सुनवाई**

जयपुर, (खलील कुरैशी) 13 नवंबर। आमजन की परिवेदनाओं के स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान के लिए मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार पंचायत समिति स्तर पर प्रतिमाह के दूसरे गुरुवार को अटल जन सेवा शिविरों का आयोजन होगा। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जिले के सभी नागरिकों को अधिकाधिक संख्या में अटल जन सेवा शिविर का लाभ लेने की अपील की है ।गुरुवार, 14 नवंबर को पंचायत समिति परिसर में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ सुबह 10 बजे से सांय 4:30 बजे अथवा जनसुनवाई पूर्ण होने तक निरंतर ब्लॉक स्तर पर अटल जन सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी जिले के दौरे पर रहेंगे तथा पंचायत समिति पर आयोजित अटल जन सेवा शिविर का निरीक्षण करेंगे। साथ ही राज्य स्तर से भी वीसी. एवं औचक निरीक्षण दलों के माध्यम से समीक्षा की जाएगी ।जिन उपखंड मुख्यालयों पर एक से अधिक पंचायत समितियां है, ऐसी स्थिति में दूसरी पंचायत समितियों पर अटल जन सेवा शिविरों का आयोजन आगामी कार्य दिवसों पर किया जाएगा। गुरुवार को राजकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को उक्त शिविर आयोजित होंगे। उक्त शिविरों में प्रत्येक नागरिक अपनी जन समस्या प्रस्तुत करते हुए उनका मौके पर समाधान प्राप्त कर सकेंगे। असंतुष्ट परिवादियों को संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर से वास्तविक कारणों से अवगत कराते हुए समझाइश करते हुए संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। शिविरों में जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

संस्थागत तंत्र विकास पर आरपीए में गुरुवार को होगा एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन

- केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड के पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे संवाद

चमकता राजस्थान। जयपुर (खलील कुरैशी) 13 नवंबर। संसाधन तंत्र विकास (Institutional Mechanism Development) पर गुरुवार 14 नवंबर को राजस्थान पुलिस अकादमी में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यालय शाला में केंद्रीय एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड के अधिकारियों के साथ संवाद कर बेहतर समन्वय के लिए चर्चा करेंगे अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी एस सेंगाथिर ने बताया कि गुरुवार को आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य जनवरी 2024 में जयपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक सम्मेलन के एजेण्डा बिन्दु संख्या 36 की पालना में केन्द्रीय पुलिस संगठनो एवं राज्य पुलिस के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना है। एडीजी सेंगाथिर ने बताया कि इस कार्यशाला में केन्द्रीय एजेन्सीज के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगें। जिसमे एक दूसरे के समन्वय के साथ बेहतर कार्य करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी।

''नवाचार से भूजल प्रबंधन'' विषय पर गुरुवार को आयोजित होगी राज्य स्तरीय कार्यशाला

चमकता राजस्थान। जयपुर! (खलील कुरैशी) 13 नवम्बर। राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, अटल भूजल योजना जयपुर द्वारा राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला ''नवाचार से भूजल प्रबंधन'' विषय पर गुरुवार, 14 नवम्बर को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा, जयपुर में आयोजित होगी। कार्यशाला के मुख्य अतिथि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी होंगे, जबकि प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग भास्कर आत्माराम सावंत अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यशाला की शुरूआत प्रातः 9:30 बजे दीप प्रज्जवलन के साथ होगी। पूरे दिन चलने वाली इस कार्यशाला में जल बचत की विभिन्न पद्धतियों को उपयोग में लेकर व 'नवाचार से भूजल प्रबंधन' द्वारा जल बचत को बढ़ाने के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही जन सहभागिता से जल बचत के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक जन समुदाय में जागरूकता लाने के बारे में चर्चा की जाएगी।

राइजिंग राजस्थान से सम्बंधित चिकित्सा विभाग की प्री-समिट गुरूवार को

- स्वास्थ्य सेवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस सहित अन्य क्षेत्रों में होंगे एमओयू:- गायत्री राठौड़

चमकता राजस्थान। जयपुर! (खलील कुरैशी) 13 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार प्रातः 11 बजे होटल आईटीसी राजपूताना में राइजिंग राजस्थान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से हैल्थ प्री-समिट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर सहित चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े उद्यमी एवं निवेशक तथा अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे।चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 'इन्वेस्ट इन हैल्थ, इनोवेट फॉर हॉलिस्टिक फ्यूचर' थीम पर आयोजित इस प्री-समिट में स्वास्थ्य सेवा, फार्मा, एवं मेडिकल डिवाइस निर्माण से जुड़ी कंपनियों के एंटरप्रेन्योर्स एवं राज्य के स्वास्थ्य विभाग, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में हैल्थ सेक्टर में निवेश के लिए निवेशकों में खासा उत्साह है। राजनिवेश पोर्टल पर बड़ी संख्या में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग से संबंधित निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

हैल्थ प्री-समिट के उद्घाटन सत्र में आयुर्वेद विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा स्वागत उद्बोधन देंगे। इंडो यूरोपियन सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के चेयरमैन प्रो. विवेक गुप्ता, आंध्रप्रदेश मेडटेक लिमिटेड के सीईओ अतुल कोटवाल निवेश के अवसरों पर प्रजेंटेशन देंगे। साथ ही केन्द्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी उद्बोधन देंगे। इसके बाद हैल्थ सेक्टर में निवेश के विभिन्न कंपनियों के साथ एमओयू किए जाएंगे उल्लेखनीय है कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, विकास एवं विस्तार की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में विकास को गति मिलने के साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में हेल्थकेयर सर्विसेज, फार्मा, मेडिकल डिवाइस निर्माण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेशकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बने।

रा शि संघ राष्ट्रीय उप शाखा वैर की मीटिंग हुई सम्पन्न

चमकता राजस्थान/वैर (राजवीर सिंह)। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा वैर की मीटिंग का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वैर में किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्य प्रकाश शर्मा अध्यक्ष उपशाखा वैर द्वारा की गई जिसमें मुख्य अतिथि मानसिंह शेरगढ़ जिला अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि सत्य प्रकाश शर्मा अध्यक्ष उप शाखा बयाना व मनमोहन शर्मा एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य रामकिशन गुर्जर राम सिंह गुर्जर के सानिध्य में मां सरस्वती पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया बैठक में जिला शैक्षिक सम्मेलन का फीडबैक लिया गया तथा शिक्षक समस्याओं पर अध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा बैर के द्वारा अपना उद्बोधन दिया गया जिसमें ओल्ड पेंशन को पूर्णतया लागू करना तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला करना मुख्य अतिथि मानसिंह शेरगढ़ द्वारा 17 नवंबर को महिला संगोष्ठी में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को भेजने का आग्रह किया तथा संगठन हित में कार्य करने पर जोर दिया कार्यक्रम में नेम सिंह फौजदार विनोद धाकड़ फूल सिंह बिजानिया विजय सिंह गुर्जर यतीश सैनी राहुल धाकड़ राकेश मीणा ममता मीना प्रधानाचार्य दारा सिंह मुकेश कुमार अग्रवाल आदि सदस्य उपस्थित हुए बैठक का संचालन मंत्री उमाशंकर राय के द्वारा किया गया।

पूर्णिमा महास्नान के साथ 15 को होगा विश्व प्रसिद्ध पुष्कर के धार्मिक मेले का समापन

सरोवर में साधु संतों का शाही स्नान आज, देशी-विदेशी सैलानी खेलकूद प्रतियोगिता में दिखा रहे दमखम

चमकता राजस्थान

जयपुर/पुष्कर (खलील कुरैशी)! तीर्थनगरी पुष्कर में चार दिवसीय पंचतीर्थ धार्मिक मेले के दौरान गुरुवार ब्रह्म चतुर्दशी को संत शाही स्नान करेंगे। 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के महास्नान के साथ ही पंचतीर्थ स्नान और धार्मिक मेला का समापन होगा। कार्तिक माह के चार दिवसीय धार्मिक मेले के चलते बुधवार को पुष्कर सरोवर में दूसरा पंचतीर्थ स्नान हुआ। सरोवर में दूर-दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। पुराणोक्त मान्यता अनुसार स्नान के बाद धर्मप्रमियों ने सरोवर की परिक्रमा लगाई तथा ब्रह्मा, नए रंगजी, पुराने वेणुगोपाल, अटमटेश्वर वराह मंदिर सहित मुख्य मंदिरों में दर्शन किए। मेला मैदान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को मुंह

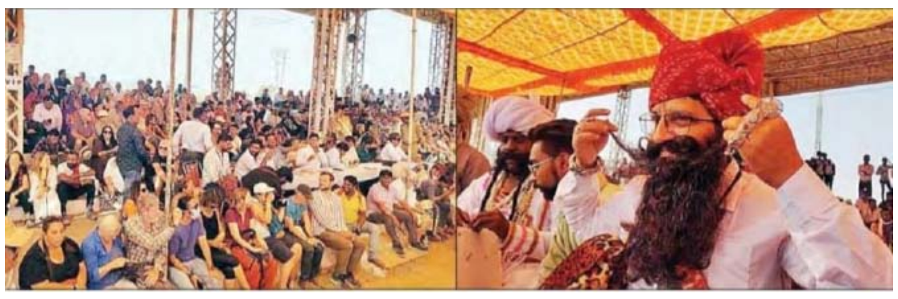

प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बढ़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक बढ़चढ़ कर भाग ले रहे है। धार्मिक मेले में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर पुलिस व प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। शाही स्नान आज: गुरुवार को ब्रह्म चतुर्दशी के उपलक्ष्य में शाही स्नान के लिए पुष्कर के विभिन्न आश्रम एवं मठ-मंदिरों में ठहरे साधु-संत निंबार्क पीठाधीश्वर जगतगुरू श्याम शरण देवाचार्य, रमैयाराम आश्रम के महंत प्रेमानंद महाराज, सेन भक्ति पीठाधीश्वर अचलानंद महाराज, श्री रामसखा पीठाधीश्वर महंत नंदराम शरण महाराज, लक्ष्मी नृसिंह मंदिर के महंत श्याम शरण महाराज, गिरिशानंद अष्टम के महंत रामानंद शास्त्री, संत गुलाबदास आश्रम के राजाराम महाराज, संत समाज के कोतवाल मंगलगिरी महाराज के सानिध्य में सरोवर के पवित्र घाटों पर हजारों संतो महात्माओं के साथ शाही स्नान करेंगे। प्रवक्ता हरिप्रसाद पाराशर ने बताया कि शाही स्नान के बाद संत रामधुनी करते हुए सरोवर की परिक्रमा लगाएंगे। ब्रह्म वैकुंठ चतुर्दशी के पवित्र मौके पर सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व की धार्मिक मान्यता के चलते साधु संतो सहित श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ेगा । प्रशासन अलर्ट मोड़ पर: संतो के शाही स्नान को देखते पुलिस व जिला प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है। संतो के आश्रमों से सरोवर जाने वाले मार्ग सुरक्षा यातायात व्यवस्था को दुरस्त किया जाएगा। वहीं घाटों पर पुलिस व्यवस्था कड़ी की जाएगी। शाही स्नान को देखते जिला व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने सरोवर की व्यवस्था का जायजा लिया व वहां तैनात अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए।पुष्कर मेले में 10.33 करोड़ के

52 घाटों पर होगी महाआरती एवं दीपदान आज

» पुष्कर। ब्रह्म चतुर्दशी गुरुवार शाम गोधूलिक वेला में पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर महाआरती आयोजित की जाएगी, जिसमें उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी शिरकत करेंगी। मुख्य रूप से ब्रह्म घाट पर पंडित मेवेंद्र पाराशर, गऊ घाट पर पंडित कैलाश मिश्र गणगौर घाट पर पंडित राहुल पाराशर, बद्री घाट पर पंडित शशांक पाराशर, वराह घाट पर पंडित रवि कांत शर्मा व जयपुर घाट पर पंडित चंद्र शेखर गौड के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक उत्सवों पर दैनिक महाआरती की जाती हैं। अयोध्या सरयू नदी पर महाआरती की तर्ज पर पुष्कर मेले में प्रशासनिक तौर पर पहली बार महाआरती होगी। महाआरती करने के लिए सदाचारी व वैष्णव आचार विचार खानपान वाले पंडितों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पशु बिक्रः पुष्कर पशु मेले में पशुओं की आवक के साथ-साथ पशुओं की खरीद-फरोख्त का बुधवार को भी दौर जारी रहा। मेले में अब तक 5 हजार 16 अश्व, 3 हजार 202 ऊंट सहित कुल 8 हजार 218 पशु-ओं की आवक हुई है, इनमें से 810 अश्व और 289 ऊंट सहित करीब 1115 मवेशियों की खरीद-फरोख्त हुई है, जिससे पशुपालकों के बीच 10 करोड़ 33 लाख से अधिक का कारोबार हुआ है। एक तरफा रहेगा यातायात व्यवस्था पुष्कर मेले में उमड़ने वाले जनसैलाब को देखते गुरुवार से नगर के मुख्य बाजार सहित ब्रह्मा मंदिर में एक तरफा यातायात व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से बलिया बांध कर बेरीकेटिंग की जायेगी।

बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

एपीसीआर ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिये गये बुलडोजर पर दिशा-निर्देशों का स्वागत किया

चमकता राजस्थान

जयपुर/नई दिल्ली!(खलील कुरैशी) 13 नवंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि केवल आपराधिक आरोपों या सजा के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि बिना उचित प्रक्रिया अपनाए और बिना स्पष्ट कारण बताए संपत्तियों का ध्वस्तीकरण अवैध है और इस तरह का कोई भी कदम कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। साथ ही, अदालत ने यह निर्देश दिया कि सार्वजनिक अधिकारी जो मनमाने तरीके से कार्रवाई करते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी की, *कानून अपने हाथ में लेने वाले अधिकारियों को जवाबदेही से बांधा जाना चाहिए।

*कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

- *नोटिस और अपील का अधिकार*: प्रभावित पक्ष को ध्वस्तीकरण आदेशों को चुनौती देने या संपत्ति खाली करने के लिए एक निश्चित अवधि में सूचना दी जाएगी।
- *कारण बताओ नोटिस अनिवार्य*: प्रस्तावित ध्वस्तीकरण से पहले 15 दिन का कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य है, जो कि नोटिस प्राप्ति के बाद ही मान्य होगा।
- *डिजिटल पोर्टल की स्थापना*: तीन महीनों के भीतर एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां सभी ध्वस्तीकरण नोटिसों की जानकारी उपलब्ध होगी, जैसे नोटिस की तिथि, कारण, और सुनवाई की तिथि। इसका उद्देश्य अवैध नोटिसों और पिछली तारीख के नोटिसों के दुरुपयोग को रोकना है।
- *व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर*: नामित अधिकारी के समक्ष प्रभावित पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
- *केवल अनिवार्य ध्वस्तीकरण*: केवल उन्हीं अवैध निर्माणों के भागों को ध्वस्त किया जाएगा, जो अनिवार्य रूप से हटाए जाने योग्य हों।
- *सुनवाई का निष्कर्ष*: सार्वजनिक सुनवाई का निष्कर्ष एक सुसंगत आदेश के रूप में आएगा, जिसमें गृहस्वामी के तर्क, प्राधिकरण के निष्कर्ष और ऐसे संपत्ति क्षेत्रों का विवरण शामिल होगा जो अनिवार्य रूप से ध्वस्त किए जाने योग्य हैं।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक आरोप हो और उसी प्रकार की अन्य संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया गया हो, तो इस प्रकार का ध्वस्तीकरण अवैध माना जा सकता है। यदि ध्वस्तीकरण कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उनके वेतन से पुनर्निर्माण की लागत और अन्य हर्जाना लिया जाएगा। इन निर्देशों का उल्लंघन होने पर अवमानना कार्यवाही और अभियोजन भी शुरू किया जाएगा।

चुनावी ड्यूटी छोड़ने पर राजस्थान आईपीएस किशन सहाय संस्पेंड

- झारखंड से बिना बताए लौट आए थे जयपुर

चमकता राजस्थान। जयपुर (खलील कुरैशी)। चुनावी ड्यूटी छोड़कर घर लौटकर आने के मामले में चुनाव आयोग ने राजस्थान कैडर के एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया। आईपीएस अधिकारी किशन सहाय मीणा आईजी मानवाधिकार के पद पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय में तैनात थे। विधानसभा चनाव के दौरान उनकी ड्यूटी झारखंड में लगाई गई थी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव राजस्थान को पत्र भेजा है।चुनाव आयोग ने पत्र में लिखा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में किशन सहाय मीणा को गुमला जिले के 67-सिसई, 68-गुमला और 69-बिशुनपुर में पुलिस ऑब्जर्वर (पर्यवेक्षक) लगाया था। आयोग की

स्वीकृति के बिना 28 अक्टूबर 2024 को किशन सहाय ने ड्यूटी स्थल छोड़ दिया। पुलिस पर्यवेक्षक की नियुक्ति चुनाव आयोग भारत के संविधान के तहत करता है। किशन सहाय का नाम राजस्थान सरकार की ओर से 21 अक्टूबर को भेजा गया था। किशन सहाय के आदेश 23 अक्टूबर को किए गए थे। उन्हें नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन से एक दिन पहले 24 अक्टूबर को निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। उन्हें फॉर्म 17ए की जांच और पुनर्मतदान हो तो उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के आदेश दिए हुए थे। उन्होंने 28 अक्टूबर को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दिया था। आयोग की मंजूरी लिए बिना जयपुर चले गए थे। इसे चुनाव आयोग ने गंभीर माना। इस पर मुख्य सचिव और डीजीपी को 11 नवंबर को पत्र जारी कर सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। आईपीएस अधिकारी किशन सहाय प्रमोटी आईपीएस अधिकारी हैं। साल 2013 में आईपीएस बने थे। अगस्त 2013 में इन्हें एसपी टोंक लगाया गया था। लेकिन 11 जनवरी 2014 को वहां से एसपी जीआरपी अजमेर लगाया गया था। यहां किशन सहाय पूरे एक साल तक रहे। इसके बाद उन्हें सरकार ने एपीओ कर दिया था। करीब 6 महीने एपीओ रहने के बाद सरकार ने किशन सहाय को सीआईडी सीबी में एसपी लगाया। किशन सहाय यहां साढ़े 4 साल तक रहे। सीआईडी सीबी के बाद जेल और फिर दोबारा सीआईडी सीबी में लगाया गया। साल 2020 में किशन सहाय को डीआईजी आर्मड बटालियन पुलिस मुख्यालय में लगाया गया। यहीं पर सहाय डीआईजी से आईजी बने। 2023 में किशन सहाय को 'मन राइट्स में लगाया गया था। जानकारी के अनुसार आईपीएस किशन सहाय पहले भी विवादों में रहे हैं। उन्होंने धार्मिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि धर्म ग्रंथों में जिसका भी वर्णन कर रखा है, वह कल्पना मात्र की बातें हैं।

एसडीआरएफ ने पार्वती नदी में डूबी युवती के शव को किया बरामद

चमकता राजस्थान

धौलपुर(रामदास तरुण) धौलपुर, 13 नवम्बर को ग्राम कैलाशपुरा के समीप पार्वती नदी में एक युवती के डूबने की सूचना पर एसडीआरएफ कंट्रोल रूम द्वारा एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू टीम प्रभारी 11 जवानों की टीम तथा आपदा राहत उपकरणों के साथ घटना स्थल पर पहुँचे। टीम कमाण्डर ने स्थिति का जायजा लिया तथा एसडीआरएफ कमांडेंट को बताया कि 12 नवम्बर को प्रातः समय ग्राम कैलाशपुरा के समीप

पार्वती नदी में चार युवतियां नहाने गई थी जो गहरे पानी में जाने के कारण चारों युवतियां डूबने लगी। ग्रामीणों के द्वारा तीन युवतियों को सकुशल बचा लिया गया, किन्तु एक युवती गहरे पानी में जाने के कारण डूब गयी। रेस्क्यू टीम के द्वारा 13 नवम्बर को प्रातः 08:15 बजे से पार्वती नदी में पुनः सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम ने मोटर बोट, बांस, बिलाई तथा रेस्क्यू रोप की सहायता से गहन सर्च किया। अथक परिश्रम तथा कड़ी मेहनत से टीम द्वारा प्रातः 10:00 बजे नदी में डूबी युवती सरिता पुत्री श्री भगवान सिंह बघेल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम कैलाशपुरा के शव को बरामद कर स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया।

नरेश मीणा जबरन मतदान केंद्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे; गुढ़ा का बूथ कैप्चरिंग का आरोप

देवली-उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा

चमकता राजस्थान

जयपुर (खलील कुरैशी)। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। इससे पहले दिनभर हुई वोटिंग के दौरान कई विवाद भी सामने आए है।देवली-उनियारा विधानसभा के समरावता में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को अमित चौधरी के थप्पड़ जड़ दिया। मीणा की वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से भी हाथापाई हुई। नरेश मीणा पर जबरन पोलिंग बूथ में घुसने का आरोप है। वहीं, नरेश मीणा का कहना है कि इस गांव के लोगों की उपखंड मुख्यालय बदलवाने की मांग है। इसलिए उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी

जबरन लोगों को धमकाकर वोट डलवा रहे थे। इसी बात का विरोध उन्होंने किया था।वहीं, झुंझुनूं के कलां गांव में फर्जी वोटिंग के विवाद में मारपीट हो गई। दावा किया जा रहा है कि निर्दलीय कैंडिडेट राजेंद्र गुढ़ा के एजेंट ने दूसरे प्रत्याशी के फर्जी वोटर को रोकने की कोशिश की तो दोनों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पोलिंग पार्टी ने स्थिति संभाली। पूर्व मंत्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा ने प्रशासन पर फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप आरोप लगाते हुए कहा- 23 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे इनमें देवली-उनियारा सीट पर सबसे ज्यादा 3.02 लाख वोटर्स हैं। उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। सातों सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 69 कैंडिडेट मैदान में है। उपचुनाव के नतीजे सरकार और विपक्ष दोनों के सियासी नरेटिव को तय तय करेगा। पांच सीट खींवसर, सलूंबर, चौरासी, देवली-उनियारा और झुंझुनूं सीट पर कांटे की टक्कर है। इन चुनावों में हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा जैसे राजनीतिक दिग्गजों की भी सियासी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्योंकि खींवसर से हनुमान बेनीवाल की पत्नी और दौसा से किरोड़ीलाल के भाई चुनावी मैदान में हैं प्रशासन और पुलिस मिली हुई है। बूथ कैप्चर कर रखा है, वोट डालने नहीं दिए जा रहे हैं। इधर, खींवसर के कुचेरा में मतदान के दौरान एक बुजुर्ग कालूलाल घांची (68) को हार्टअटैक आ गया। बूथ पर मौजूद पुलिस के जवान अर्जुनलाल ने सीपीआर देकर उनकी जान बचाई। उपचुनाव की 7 सीटों पर शाम 5 बजे तक करीब 64.75 फीसदी वोटिंग हुई है।चुनावी ड्यूटी छोड़कर आए राजस्थान के आईपीएस सस्पेंड: झारखंड से बिना बताए जयपुर आ गए थे; पहले भी विवादों में रह चुके किशन सहाय जयपुर। चुनाव आयोग ने राजस्थान कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी किशन सहाय को सस्पेंड कर दिया। किशन सहाय मीणा आईजी मानवाधिकार के पद पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय में तैनात थे। विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी ड्यूटी झारखंड में लगाई गई थी।इस संबंध में चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव राजस्थान को पत्र भेजा है।

संक्षिप्त समाचार

अतिरिक्त रोल पर्यवेक्षक डॉ. जोगाराम लेंगे ईआरओ एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

चमकता राजस्थान। धौलपुर(रामदास तरुण)। धौलपुर, 13 नवम्बर। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त रोल पर्यवेक्षक डॉ. जोगाराम, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में 14 नवम्बर को प्रातः 9:30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी। अतिरिक्त रोल पर्यवेक्षक डॉ. जोगाराम का दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में यह प्रथम भ्रमण है। उनका द्वितीय भ्रमण दावे एवं आपत्तियां निस्तारण करने की अवधि 29 नवम्बर से 24 दिसम्बर के मध्य होगा तथा तृतीय भ्रमण पूरकों का मुद्रण एवं अंतिम प्रकाशन की अवधि में 25 दिसम्बर से 6 जनवरी के मध्य होगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं से 28 नवंबर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। आगामी 23 नवंबर को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर समिति के साथ बैठक कर पठन एवं सत्यापन किया जाएगा। 24 नवंबर को मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान के तहत राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे आपत्तियों के आवेदन लिए जाएंगे। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 24 दिसंबर तक किया जाएगा। एक जनवरी 2025 को हेल्थ पैरामीटरों की जांच एवं अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति के बाद डेटाबेस को अपडेट एवं पूरक का मुद्रण किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा। मतदाता सूची के संबंध में कोई शिकायत अथवा जानकारी हेतु टोल फ्री न 1950 अथवा ईआरओ कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

राज्य सब जूनियर हैंडबॉल के लिये जयपुर टीमे घोषित

- **अजय राज यादव और एकता कंवर को कप्तानी**

चमकता राजस्थान/जयपुर, 13 नवंबर। जालोर में 14 से 17 नवंबर तक होनी वाली 29वी राजस्थान राज्य सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता-2024-25 में भाग लेने वाली जयपुर बालक एवं बालिका टीमों की घोषणा कर दी है। जयपुर ज़िला हैंडबॉल संघ के सचिव अरुण प्रताप सिंह ने बताया की बालक टीम का कप्तान अजय राज यादव को बनाया गया है, जबकि बालिका टीम की कमान एकता कंवर को दी गई है।

टीमें: बालक वर्ग:- अजय राज यादव (कप्तान), यश यादव, अमन जांगिड, नितिन सैनी, विशाल कुमार प्रजापत, रोशन यादव, नाहर सिंह, विक्रम गुर्जर, अजय सराधना, रमेश कुमार बाजिया, हनुमान मीणा, मनीष जैन। **बालिका वर्ग:-** एकता कंवर (कप्तान), अन्नू, वर्षा जाखड़, भावना, काजल कंवर, काजल गुर्जर, ब्यूटी कुमारी, एंजेल बैद, पावनी खुराना, अन्विता चौधरी, मिष्टी सुकलेचा, निशा गुर्जर।

बंशीवाल सेवा-धर्म फाउंडेशन द्वारा 11 नवविवाहित जोड़ों का विवाह संपन्न

चमकता राजस्थान। भरतपुर (राजवीर सिंह) बंशीवाल सेवा-धर्म फाउंडेशन द्वारा देवउठनी ग्यारस पर 11 नवविवाहित जोड़ों का उनकी रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। उक्त सम्मेलन का कार्यक्रम लक्ष्मण वाटिका मैरिज होम, भरतपुर में कराया गया जिसमें मुख्य अतिथि बनय सिंह अध्यापक द्वारा संस्था के कार्यों की सराहना की गई एवं उनके द्वारा नवविवाहित जोड़ों को आर्शीवाद दिया गया।
संस्था के उपाध्यक्ष हरिओम पोहिया द्वारा कार्यक्रम का संचालन कर आगामी सम्मेलन 02 फरवरी 2025 (बसंत पंचमी) को कराया जायेगा के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर पुष्पेन्द्र बंशीवाल, राकेश जया, अमित बंशीवाल, पंकज बंशीवाल, दिगम्बर कुम्हेर, दिनेश सूपावस, रजत, डॉ० निधि गोडेला, शुभम चाहर,मुनीम बंशीवाल,करतार बंशीवाल आदि लोग उपस्थित रहे।

महिला थाने में एसीबी कार्यवाही के बाद पुलिस अधीक्षक ने एसएचओ और रीडर को किया सस्पेंड

चमकता राजस्थान। भरतपुर (राजवीर सिंह) महिला थाने में मंगलवार को एसीबी कार्रवाई के बाद भरतपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने एसएचओ भंवर सिंह और रीडर जय सिंह को सस्पेंड कर दिया है। इनमें से एसएचओ भंवर सिंह मार्च 2025 में सेवानिवृत्त होने वाला था। कार्रवाई के दौरान रीडर कक्ष की अलमारी से 4,54,700 रुपए और एसएचओ के क्वार्टर से 1,17,000 रुपए बरामद हुए थे। जिसके बाद एसपी ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि महिला थाना के एसएचओ भंवर सिंह और रीडर जय सिंह को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार एसएचओ भंवर सिंह मार्च 2025 में सेवानिवृत होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही एसीबी की कार्रवाई में महिला थाने और एसएचओ के क्वार्टर से बड़ी रकम की बरामदगी हुई है। सेवानिवृत्ति से पहले इतनी बड़ी रकम बरामदगी के चलते यह पूरा घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि मंगलवार को एसीबी की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर महिला थाने में छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान महिला थाने के रीडर कक्ष की एक अलमारी से 4,54,700 रुपए और थाना प्रभारी भंवर सिंह के क्वार्टर से 1,17,000 रुपए बरामद किए गए। नोटों के 15 बंडल बने हुए थे और प्रत्येक बंडल पर नंबर अंकित थे, जो कि संभवतः मुकदमों के नंबर थे। फिलहाल एसीबी की टीम पूरे मामले में पड़ताल करने में जुटी हुई है।

किशनगढ पंचायत समिति में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन का दिया वर्चुअल प्रशिक्षण

ई पंचायत पर स्वामित्व के दस्तावेज की जानकारी होगीं अपलोड, ग्रामीण आबादी भूमि का रिकार्ड होगा ओनलाईन

चमकता राजस्थान

रघुनंदन पारीक /श्रीनगर :-अजमेर/ मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर के आदेशानुसार स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों, का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रखा गया। प्रशिक्षण की शुरूआत में रेखा मीणा - विकास अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रेल 2020 के अवसर पर सरकार द्वारा स्वामित्व योजना आरम्भ की गई। सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और समाज पर दूरगामी प्रभाव को देखते हुए इस योजना का क्रियान्वयन पंचायतीराज विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयासो से किया जा रहा है।
दक्ष प्रशिक्षक नन्दकिशोर कुमावत-सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति किशनगढ ने बताया कि सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और समाज पर दूरगामी प्रभाव को देखते हुए इस योजना का क्रियान्वयन पंचायतीराज विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयासो से किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत की है । इस योजना के तहत लाभार्थी ग्रामीणों को पट्टा/विक्रय विलेख एवं रजिस्ट्री भौतिक रूप से देने के साथ-साथ दस्तावेजों की पीडीएफ फाईल बनाकर लाभार्थी के मोबाईल नंबर पर भी प्रेषित की जावेगी। ग्रामीण आबादी भूमि का रिकार्ड ओनलाईन होगा। इस योजना के तहत, आवेदकों को गांवों के घरों में बैंक ऋण जल्दी मिल जाएगा। यह योजना ग्रामीण लोगों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करेगी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे। ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को उनके घरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। सरकार गांवों में ड्रोन का उपयोग करके डिजिटल सर्वेक्षण किया जावेगा और पात्र लोगों को स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा। गांवों में विकास की गति को तेज देने के लिए दो वेब पोर्टल, ई-ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना शुरू किया गया है। ग्रामों में संपत्तियों की मैपिंग में स्वामित्व योजना ड्रोन का उपयोग से होगी। इससे संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। पोर्टल ग्रामीणों को बैंकों से ऋण लेने में आसान बनाने में मदद करेगा। इस स्कीम के तहत आवासीय संपत्ति के मालिकों को सरकार से आवासीय कार्ड मिलेंगे। स्वामित्व योजना में गांवों में भूमि के स्वामित्व का रिकॉर्ड तैयार होता है, जो कर संग्रह, भवन निर्माण स्वीकृति, भूमि उपयोग किस्म परिवर्तन, भूमि नाम हस्तान्तरण में सहयोग करेगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा भूमि का मैपिंग किया जाता है। भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी। स्वामित्व योजना के तहत गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजीटल मानचित्र तैयार किये जाकर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को सौपें जायेगे। गावों की आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य और मानचित्रण कार्य पूरा होने पर ग्राम पंचायतों के द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति को पटटा दिया जावेगा।
स्वामित्व योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम की आबादी भूमि का मानचित्र ड्रोन के जरिये फोटोग्राफी तैयार की गई, फोटोग्राफी के उपरान्त भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त मैप 1.0 में इमेजों अनुसार प्रत्येक भूखण्ड एवं निर्मित भवन का सर्वे- ग्राम स्तरीय सर्वे समिति- ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ट सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, संबंधित राजस्व ग्राम के वार्ड पंचों की समिति द्वारा किया जावेगा। सर्वे समिति द्वारा उस सम्पत्ति के मालिक का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड संख्या, मोबाईल नम्बर, उस भूखण्ड की दिशाओं की स्थिति, क्षेत्रफल इत्यादि की जानकारी संकलित की जावेगी। सर्वे समिति द्वारा सर्वेक्षण कार्य कर, ग्रामीणों की आपत्तियों का निस्तारण पंचायत कोरम, विशेष ग्राम सभा में निस्तारण कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को फाईनलाईज मैप हेतु भेजा जावेगा।फाईनलाईज मैप को एवं सूचियों को ग्राम पंचायत मे आज जन के अवलोकनार्थ रखा जावेगा। इसके आधार पर संबंधित लाभार्थियों को राजस्थान पंचायतीराज नियम-1996 के अनुसार पटटा रजिस्ट्री करवा कर दी जावेगी।
प्रशिक्षण के दौरान पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त ग्राम विकास अधिकारी, उपस्थित रहे।

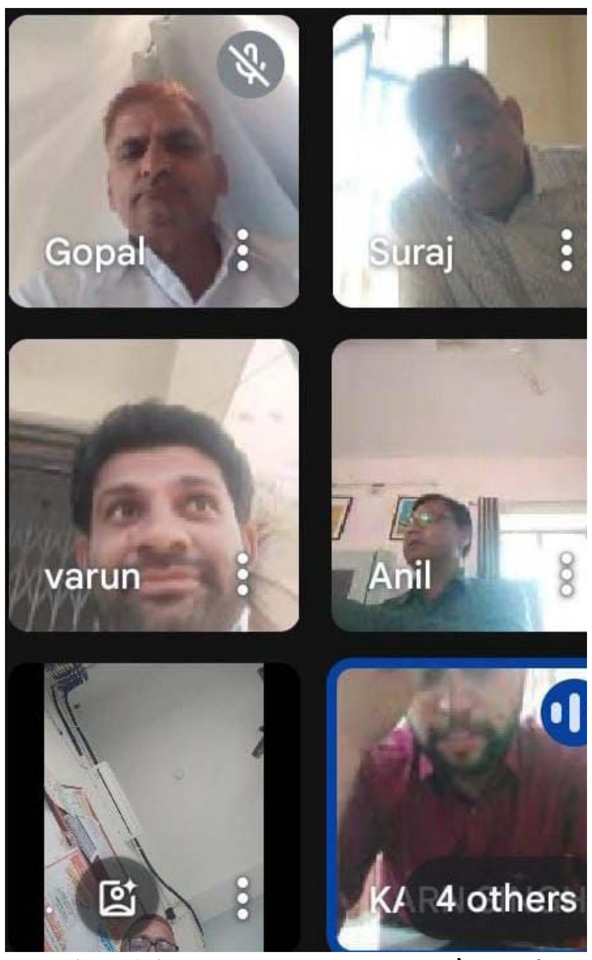

राजस्थान राज्य सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता आज से

- **बालक एवं बालिका वर्ग खेला जायेगा यह टूर्नामेंट**
- **जालोर में आयोजित होगी यह चार दिवसीय चैंपियनशिप**
- **कुल 40 टीमे लेगी भाग**

चमकता राजस्थान

जयपुर, 13 नवंबर। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के तत्वावधान में जालोर ज़िला हैंडबॉल संघ द्वारा 29वी राजस्थान राज्य सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता (बालक व बालिका)-2024-25 का आयोजन 14 से 17 नवंबर तक जालोर में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 40 टीमे जिसमें बालक वर्ग में 24 एवं बालिका वर्ग में 16 टीमे भाग ले रही है।
राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के मानद सचिव यश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता लीग कम नॉक आउट आधार पर खेली जायेगी। प्रतियोगिता के लिये पाँच ग्राउंड तैयार किये गये है। जिन पर बालक वर्ग में 72 एवं बालिका वर्ग में 36 मैच खेले जायेंगे। प्रतियोगिता के दौरान ही आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के राज्य बालक एवं बालिका टीमों के लिए 30-30 संभावितों का भी चयन चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

बालक एवं बालिका वर्ग की टीमों को चार चार पूल में बाँटा गया है। बालक वर्ग:- पूल एः- जयपुर, ज्ञान ज्योति अकादमी, अजमेर, झालावाड़, डूंगरपुर एवं सिरोही। पूल बीः- श्रीगंगानगर, चूरू, दुलमाना हैंडबॉल अकादमी, माही हैंडबॉल अकादमी एवं झुंझुनू, सवाईमाधोपुर। पूल सीः-सीकर, भोम सिंह हैंडबॉल अकादमी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ एवं करौली। पूल डीः-एसटीसी नोजगे, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, जालौर एवं महाराणा प्रताप हैंडबॉल अकादमी।
बालिका वर्गः- पूल एः- श्रीगंगानगर, अलवर, झुंझुनू एवं बीकानेर। पूल बीः-हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर एवं सीकर। पूल सीः- जयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर एवं महाराणा प्रताप हैंडबॉल अकादमी। पूल डीः- जोधपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू एवं दुलमाना हैंडबॉल अकादमी।

'साझेदारी, सहयोग और समन्वय से कचरे को कम करके संसाधनों का कुशल उपयोग बढ़ाया जा सकता है' : मनीष पारीक

चमकता राजस्थान। जयपुर से संवाददाता/ खलील कुरेशी। जयपुर, 13 नवम्बर 24 को जयपुर नगर निगम के पूर्व उप महापौर मनीष पारीक ने कट्स द्वारा आयोजित ग्रीन एक्शन वीक कार्यक्रम में कहा कि साझेदारी, सहयोग और समन्वय के माध्यम से हम कचरे को कम कर सकते हैं। संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, और समाज में समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत प्रथाओं के प्रति जागरूकता फैलाना था, जिसमें विभिन्न स्थानीय समुदायों में प्रशिक्षण, परामर्श बैठकें और गतिविधियाँ आयोजित की गईं। पारीक ने स्थानीय समुदायों में छोटे प्रयासों की सराहना करते हुए सभी से पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने की अपील की। उन्होंने सतत प्रथाओं के प्रसार के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण पहलों में भाग लेने का आ''ान किया।ग्रीनहब के बिजनेस हेड सौरभ सिंघल ने कचरे की बढ़ती समस्या पर चर्चा करते हुए कहा कि बढ़ती खपत और कचरा उत्पन्न होने के बीच एक सीधा संबंध है। उन्होंने कचरे के पृथक्करण और उसके पुनर्चक्रण पर जोर देते हुए बताया कि गीले कचरे से खाद और गैस जैसी उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। सिंघल ने समुदायों में ठोस और गीले कचरे को अलग करने के प्रयासों को बढ़ावा देने की बात की ताकि कचरे को पुनः उपयोगी उत्पादों में बदला जा सके। वार्ड पार्षद गोविंद सिंह ने प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या और इसके निस्तारण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग जारी है, और इसके सही निस्तारण के लिए अधिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम जरूरी हैं। सुनील यादव, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स का प्रचार कर रहे हैं, ने कॉर्न-स्टार्च और गन्ने के अवशेषों से बने पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बैग्स की एक अभिनव पहल प्रस्तुत की, जिसे पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प बताया। इस परामर्श बैठक ने विभिन्न हितधारकों को विचारों और समाधानों को साझा करने का अवसर प्रदान किया, जिससे जयपुर को एक सतत और सशक्त शहर बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहन मिला। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

विधानसभा उपचुनाव में सातों विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं का आभार: सांसद संजना जाटव

कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी और भाजपा का टूटेगा अहंकार: गिरीश जौहरी

चमकता राजस्थान

भरतपुर (राजवीर सिंह) सांसद संजना जाटव ने राजस्थान में हुए सातों विधानसभा उपचुनावों को लेकर क्षेत्र के मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करके मतदाताओं को भयभीत करने और चुनाव में गड़बडी फैलाने का काम किया। भाजपा की पूरी कोशिश रही कि पुलिस -प्रशासन के बल पर मतदान प्रभावित किया जा सके। इसके बावजूद रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे।

भाजपा और चुनाव ड्यूटी में तैनात पुलिस व प्रशासनिक अमले की मिलीभगत की शिकायत चुनाव आयोग के यहाँ नियुक्त पर्यवेक्षकों को आज निरंतर की गयी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा आम जनता की सजगता और साहस के कारण भाजपा ओछे हथकंडे अपनाकर भी कामयाब नहीं सकें।
सांसद प्रतिनिधि गिरीश जौहरी ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा ने जिस तरह सत्ता का दुरूपयोग किया है। इससे भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। भाजपा का लोकतंत्र और नैतिकता में कोई विश्वास नहीं है। इसलिए मतदाताओं ने भाजपा को आज सातों विधानसभा क्षेत्रों में खारिज कर दिया है और कांग्रेस विजय प्राप्त करेंगी और भाजपा का अंहकार टूटेगा।

दीया सिटी पैलेस में कथा का निमंत्रण!

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लिया रामभद्राचार्य जी से आशीर्वाद

चमकता राजस्थान

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने श्री बालाजी गौशाला संस्थान, सालासर के सानिध्य में विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति, जयपुर द्वारा आयोजित श्रीराम कथा के भव्य कार्यक्रम में जगद्गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके श्रीमुख से रामकथा का श्रवण किया।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा है कि महाराज जी का आशीर्वाद पूरे विश्व पर बना रहे साथ ही उन्हें सिटी पैलेस में कथा के आयोजन का निमंत्रण दिया। कथा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर,उद्योग,खेल एवं युवा मामला राज्य मंत्री के के विश्नोई,राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत,जयपुर शहर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा,आयोजक मंडल एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने सांसद कोष से नवीनीकृत हुए बार एसोसिएशन सभागार का किया लोकार्पण

चमकता राजस्थान /रघुनंदन पारीक /श्रीनगर :-अजमेर

किशनगढ़ (अजमेर), 12 नवंबर 2024। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने मंगलवार को किशनगढ़ के न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन के सभागार का जीर्णोद्धार उपरांत लोकार्पण किया। इस परियोजना की 10 लाख रुपये लागत सांसद निधि से प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन दीपावली स्नेह मिलन समारोह के रूप में किया गया, जिसमें उन्होंने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दीं और उनका उत्साह बढ़ाया।

कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं के बीच आपसी सौहार्द और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित ₹एडवोकेट प्रीमियर लीग 2024₹ के विजेताओं और उपविजेताओं को भी सम्मानित किया गया। भागीरथ चौधरी

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 10 लाख रुपए के सांसद फंड से नवीनीकृत हुए किशनगढ़ बार एसोसिएशन के सभागार का किया लोकार्पण, अधिवक्ताओं ने व्यक्त किया आभार

ने प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और ट्रॉफी देकर उनकी खेल भावना की सराहना की। समारोह में अधिवक्ता समुदाय के साथ गहरा संबंध स्थापित करने और उनके प्रति समर्थन जताने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री और सांसद भागीरथ चौधरी का आभार व्यक्त किया और न्यायालय परिसर के विकास में उनके योगदान की सराहना की।

न्याय प्रणाली लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि बार एसोसिएशन के सभागार नवीनीकरण में मेरी सांसद निधि का योगदान रहा है और यह प्रयास आज मूर्त रूप में हमारे सामने है। निश्चित रूप से इस सभागार के माध्यम से अधिवक्ताओं को बेहतर संसाधन, आधुनिक सुविधाएं, और विचार-विमर्श के लिए एक सुसज्जित मंच मिलेगा। मुझे विश्वास है कि यहां से निकलने वाले विचार, बहस और मुद्दे न्यायपालिका को और भी मजबूत करेंगे और हमारे समाज को न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। भागीरथ चौधरी ने कहा कि न्याय प्रणाली हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अधिवक्ता बंधुओं का योगदान इस स्तंभ को सुदृढ़ करने में सराहनीय है। मुझे उम्मीद है कि यहां से निकले विचार, चिंतन और संवाद, देश और समाज को नई दिशा देने में मददगार होंगे।

संक्षिप्त समाचार

जियो वर्ल्ड प्लाजा में खुला टीरा का पहला लग्जरी ब्यूटी स्टोर

- 6200 वर्ग फुट में फैला है लग्जरी ब्यूटी हब

चमकता राजस्थान/मुंबई। रिलायंस रिटेल के ब्यूटी ब्रांड टीरा ने बुधवार को मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड प्लाजा में अपना पहला लग्जरी फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया। 6200 वर्ग फुट में फैला यह भव्य स्टोर शान और सुंदरता से सजा हुआ है, जहां ग्राहक दुनिया के शीर्ष ब्यूटी ब्रांड्स का अनुभव कर सकते हैं। इसमें डियोर, एस्टी लॉडर, यवेस सेंट लॉरेंट, ला मेर, प्रादा और वैलेंटिनो जैसे वैश्विक ब्रांड्स के 15 विशेष शॉप-इन-शॉप बुटीक शामिल हैं।

रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने कहा, ''टीरा में हम एक ऐसा स्थल बना रहे हैं जो भारत में लग्जरी ब्यूटी की नई परिभाषा गढ़ेगा। हमारा फ्लैगशिप स्टोर हर ग्राहक को प्रेरित, प्रोत्साहित और आनंदित करेगा। हमें इस खास सफर पर ग्राहकों का स्वागत करने की खुशी है।''

टीरा ब्यूटी सूट में विशेष फेशियल सेवाएं जैसे 'सिग्नेचर ग्लो' उपलब्ध हैं, जो त्वचा में नई चमक लाती हैं। साथ ही, टीरा कैफे में स्नैक्स और पेय पदार्थों का आनंद लिया जा सकता है। यह स्टोर भारत में लग्जरी ब्यूटी का नया मानक स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुकेश चौधरी व आशीष चौधरी राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी में लहराएंगे परचम: कोच मुकेश बोहरा

चमकता राजस्थान/जयपुर। टोंक निवाई सुरिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुकेश चौधरी व आशीष चौधरी का 17 वर्ष बालक वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर विद्यालय परिवार में सम्मान समारोह रखा गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान कनेश कुमार मीणा ने बताया कि अध्ययन के साथ-साथ विद्यालय खेलों में भी अद्वितीय स्थान रखता है। संबोधन में संस्था प्रधान ने बताया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और एक खिलाड़ी के रूप में शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है।आज के समय खेलों का विशेष महत्व है।राज्य और केंद्र सरकार के कई योजनाएं खिलाड़ियों को राष्ट्रीय ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर रही है।68वीं राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में विद्यालय के दो छात्र मुकेश चौधरी व आशीष चौधरी का चयन हुआ है, जो क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। इस अवसर पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक मुकेश बोहरा ने राष्ट्रीय खिलाड़ियों को माल्यार्पण कर मोमेंटो भेंट करते हुए विद्यालय परिवार ने सम्मानित किया। बोहरा ने बताया कबड्डी खिलाड़ी मुकेश चौधरी व आशीष चौधरी राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण शिविर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मोजमाबाद दूदू में भाग ले रहे हैं।आगामी दिनों में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में आयोजित होगी। जिसमें दोनों खिलाड़ी भाग लेंगे। कोच मुकेश बोरा ने बताया कि खेल जगत में विद्यालय का विशेष स्थान है प्रत्येक वर्ष जिला स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर इस विद्यालय के छात्र विभिन्न खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अपने विद्यालय जिला और राज्य का नाम रोशन करते हैं।

चंडीगढ़ में जल्द बनेगा हरियाणा का नया विधानसभा भवन, पंजाब से विरोध होना शुरू

चंडीगढ़/एजेंसी। हरियाणा के लिए चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है, लेकिन इसका खुद का अस्तित्व केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हैं। ऐसे में विधानसभा भवन के निर्माण को लिए प्रस्ताव की फाइल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास अटकी हुई थी। पिछले कुछ दिनों से इसमें कुछ संवेदनशील जोन को लेकर रुकावटें पैदा हो रही थीं, जो अब दूर हो चुकी हैं। हरियाणा के लिए नए विधानसभा निर्माण के लिए सबसे पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रयास शुरू किए थे। चंडीगढ़ प्रशासन ने इसके लिए जमीन देने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी। लेकिन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मंजूरी को लेकर बात अटकी हुई थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव में कुछ बदलाव के साथ इसे नए सिरे से केंद्र सरकार के पास भेजा था। इस पर अब केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रशासन के मुताबिक, जो जमीन हरियाणा की ओर से पंचकूला एरिया की मिली है, वह चंडीगढ़ के आईटी पार्क के 123 एकड़ जमीन के साथ लगती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विधानसभा की नई इमारत के लिए चंडीगढ़ की ओर से रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क को जाने वाली सड×क के पास 10 एकड़ जमीन दी जा रही है। मनसा देवी कांप्लेक्स के पास 12 एकड़ जमीन है, जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील जोन में आती है। केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही नए विधानसभा भवन के निर्माण की सभी रुकावटें दूर हो चुकी हैं। अब प्रशासन को आसानी से यह जमीन ट्रांसफर की जा सकती है। हरियाणा सरकार पहले जमीन के लिए 550 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार थी। अधिसूचना जारी होने पर पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

राजस्थान हाईकोर्ट की नई इमारत के सरकारी निर्माण में कई खामियां

आरएसआरडीसी के खिलाफ मामला दर्ज

चमकता राजस्थान

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की नई इमारत मैं कई खामियों लेकर हाईकोर्ट के कोर्ट ऑफिसर शरद जोशी ने कुड़ी भगतासनी थाने में सरकारी कंपनी राजस्थान स्टेट रोड कॉर्पोरेशन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.थाना प्रभारी रामभरोसी ने बताया कि कोर्ट ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में निर्माण में कई खामियां बताई हैं. 220 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग में पिछले दो साल से कई घटनाएं हुई हैं. फायर सेफ्टी सिस्टम की खामी देखने को मिली है. थानाप्रभारी ने बताया कि कोर्ट ऑफिसर शरद जोशी ने रिपोर्ट में बताया है कि हाईकोर्ट का नया भवन बनाने का ठेका आरएसआरडीसी लिमिटेड कंपनी को दिया गया था. कंपनी ने 2008 में निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसे बनाने में करीब 11 साल लगे. कंपनी ने 2019 में बिल्डिंग को कोर्ट के हवाले कर दिया था. इसके रख-रखाव की की जिम्मेदारी कंपनी ने ली थी. इस पर प्रति वर्ष लागत 22 लाख रुपए आ रही है. 18 सितंबर 2024 को सुबह 5 बजे कोर्ट चेम्बर-2 में आग लग गई थी. हादसे की जांच की गई तो सामने आया कि फायर सिस्टम ने आग लगने के दौरान काम ही नहीं किया. फायर सिस्टम निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं लगाया गया है.

- **कोर्ट ऑफिसर ने दी घटनाओं की सूची**

नए भवन में सुनवाई और वकीलों का बैठना भी शुरू हो गया है। ऐसे में जान-माल के नुकसान का डर बना रहता है।

जोशी ने बताया- हाईकोर्ट का कब्जा लेने के बाद इसके निर्माण में लगातार खामियां सामने आ रही है। कई चैंबरों की छत गिर गई है। दीवारों-पिलरों में दरारें आ गई है तो कई जगह लगे सरिए फूल गए हैं। 18 सितंबर 2024 को सुबह 5 बजे कोर्ट चैंबर 2 में आग लग गई थी। हादसे की जांच की गई तो सामने आया कि फायर सिस्टम ने आग लगने के दौरान काम ही नहीं किया। फायर सिस्टम निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं लगाया गया है। कोर्ट ऑफिसर का आरोप है कि बिल्डिंग बनाने में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है।

हाईकोर्ट की बिल्डिंग में दो साल में हुए ये हादसे

24 सितंबर 2024- भूतल पर स्थित गेट संख्या 3 पर मीडियेशन सेंटर के सामने स्थित लिफ्ट के पास छत गिर गई थी। 18 सितंबर 2024- सुबह 5 बजे कोर्ट चैंबर 2 में भीषण आग लग गई थी। 12 सितंबर 2024- बारिश के कारण कोर्ट रूम नंबर 2 में छत से पानी टपकने के कारण और कोर्ट रूम नंबर 16 में छत-खिड़की से पानी अंदर आने के कारण कोर्ट कार्य रोका गया। 12 सितंबर 2024 को कोर्ट रूम नंबर 19 की छत से पानी के रिसाव के कारण फॉल्स सिलिंग में पानी भर गया और फॉल्स सिलिंग गिर गई। सितंबर 2024 - लेखा (संस्थापन) शाखा में फॉल्स सीलिंग का जिप्सम बोर्ड गिर गया था। 23 जून 2023- सिविल विविध अपील अनुभाग और 28 जून को बिल अनुभाग की छत का प्लास्टर उखड़कर गिरा था। इसके कारण फॉल्स सीलिंग भी गिर गई थी। 29 अप्रैल 2023- डोम एरिया की छत का कुछ हिस्सा गिर था। 20 फरवरी 2023- शाम को 6:05 बजे चैंबर नंबर 14 की छत गिर गई। चैंबर की फॉल्स सीलिंग और अन्य फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गया। इसे पहले कोर्ट नंबर 2 और चैंबर नंबर 16 में भी ऐसी घटना हो चुकी है।

झारखंड में दो राज्यों के राज्यपालों सहित कई हस्तियों ने डाले वोट, कहा- सभी मतदाता निभाएं अपना फर्ज

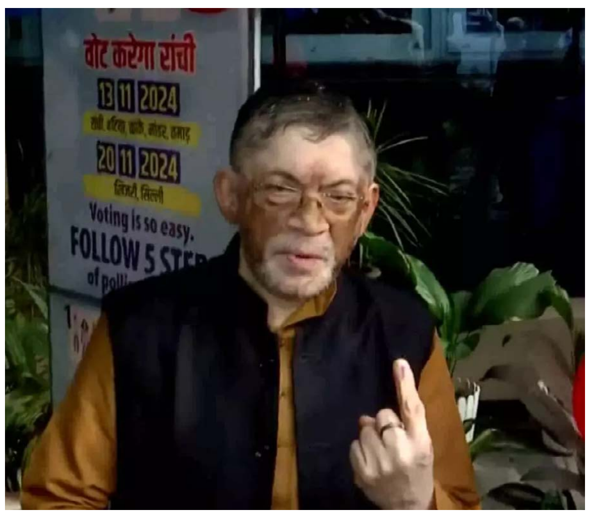

रांची/एजेंसी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के तहत 43 सीटों पर बुधवार सुबह सात बजे से मतदान जारी है। कई बड़ी हस्तियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और विभिन्न सीटों पर प्रत्याशियों ने अपने-अपने बूथों पर सुबह-सुबह मतदान किया है।

ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर क्षेत्र में मतदान केंद्र पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोट डालने पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदाता का फर्ज होता है मतदान करना, उसी के तहत आज मैंने अपने परिवार के साथ मतदान करके अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। मैं समस्त झारखंड वासियों से अपील करता हूं कि अपने परिवार के साथ अपने मत का उपयोग जरूर करें और आस-पास के लोगों को भी प्रेरित करें ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो।

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के श्री कृष्ण प्रशासनिक सेवा संस्थान में स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मतदाता मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें। अपने मताधिकार का सही से प्रयोग करना हम सबका कर्तव्य है। राज्यपाल ने कहा कि आप सभी ने देखा होगा कि जम्मू-कश्मीर में अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने मतदान किया। इसी तरह झारखंड के मतदाता भी पहले मतदान करें, उसके बाद दूसरा काम करें।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां विधानसभा क्षेत्र में अपने बूथ पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, 'मैंने राज्य को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए वोट किया है, मुझे उम्मीद है कि खरसावां की जनता भी इसी तरह वोट करेगी'

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी रांची के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद स्याही लगी अंगुली दिखाते हुए सभी लोगों से मतदान की अपील की।

केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और रांची के भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह, झामुमो की प्रत्याशी और राज्यसभा की सांसद डॉ महुआ माजी ने सुबह में अपने-अपने बूथों पर पहुंचकर वोट डाले। कोडरमा सीट पर भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री डॉ नीरा यादव अपने परिवार के साथ इंदरवा झरीटांड़ स्थित बूथ संख्या 239 पर पहुंचीं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बूथों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण से बाहर

किशनगढ़ जैसी व्यापारिक नगरी में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं करूंगा : विधायक डॉ विकास चौधरी

चमकता राजस्थान

रघुनंदन पारीक;-श्रीनगर / अजमेर-किशनगढ़ विधायक डॉ विकास चौधरी ने व्यापारियों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात, पिछले दिनों फिरोती के लिए व्यापारियों को मिली धमकी के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम सोपां पत्र व्यापारियों से की अपील, डरने की नहीं जरूरत हर कदम पर आपके साथ खड़ा हूं।

मदनगंज किशनगढ़:- किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला पुलिस अधीक्षक से पिछले दिनों व्यापारिक नगरी किशनगढ़ के व्यापारियों को कुछ लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी देकर मांगी गई फिरोती के संबंध में मुलाकात की, व्यापारियों के साथ अपना पक्ष रखा। विधायक चौधरी ने जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया की आए दिन किशनगढ़ के व्यापारियों को फिरौती के लिए धमकियां मिल रही है । पुलिस को शिकायत देने के बावजूद अभी तक ना आरोपियों को चिन्हित किया गया है ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया है । किशनगढ़ मार्बल नगरी के साथ ही हैंडीक्राफ्ट एवं टेक्सटाइल उद्योग की विश्व प्रसिद्ध मंडी है, जहां से अन्य प्रदेशों एवं देशो में व्यापार किया जाता है। विधायक चौधरी ने बताया कि ऐसे व्यावसायिक शहर में व्यापारियों को धमकियां मिलना अत्यंत चिंतनीय एवं गंभीर विषय है, व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि मैं हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हूं । जिला पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंप कर त्वरित आवश्यक कार्रवाई की मांग की । विधायक चौधरी ने भाजपा सरकार को जमकर घेरते हुए बोला कि जब से 11 महीने से इस शांतिप्रिय प्रदेश में भाजपा का राज आया है आए दिन लूट, डकैती ,फिरौती एवं महिला अत्याचार जैसी गंभीर घटनाएं चरम पर है, कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण से बाहर है । विधायक चौधरी ने किशनगढ़ के व्यापारियों से अपील की आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका विधायक हर कदम पर आपके साथ है ।पुलिस प्रशासन को चेताया कि जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करें, नहीं तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान डॉ विकास चौधरी के साथ ब्लॉक अध्यक्ष रूपनगढ़ जीवन भाकर,ब्लॉक अध्यक्ष किशनगढ़ मोहित खंडेलवाल,नगर अध्यक्ष आज़म कुरैशी,नेता प्रतिपक्ष हमीदा बनो,पार्षद महेंद्र यादव,पार्षद मोहम्मद रफीक,दीपक बिरला सहित किशनगढ़ के व्यापारी बंधु व कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे ।

भारतीय टी20 टीम में वापसी का लक्ष्य रखें : केएल राहुल

मुम्बई। एजेंसी

बल्लेबाज केएल राहुल ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ने को लेकर कहा है कि उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वह एक नई टीम से खेलना चाहते थे ताकि आजादी से खेलते हुए बेहतर प्रदर्शन कर एक बार फिर राष्ट्रीय टी20 टीम में अपनी जगह पक्की कर सकें। राहुल ने पिछले 3 सत्र में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेला है पर अगले साल होने वाले टूर्नामेंट से पहले वह टीम से अलग हो गये हैं।

अब वह इसी माह 24 और 25 नवंबर को जेद्दा में होने वाली नीलामी में उतरेंगे। राहुल को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) की रिटेन खिलाड़ियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। राहुल को जब रिटेन नहीं किया गया था तभी से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह फ्रेंचाइजी का फैसला था या खिलाड़ी का अपना। इसी को लेकर राहुल ने कहा है कि यह उनकी इच्छा थी कि वे एक नई टीम की तलाश करें और भारतीय टी20 टीम में वापसी का लक्ष्य रखें।

राहुल ने कहा मैं एक नई शुरूआत करना चाहता था। मैं अपने विकल्पों का पता लगाना चाहता था। मैं वहां खेलना चाहता था जहां मुझे कुछ आजदी मिल सके और टीम का माहौल हल्का हो। इसके लिए कभी-कभी, आपको दूर भी जाना पड़ता है और अपने लिए कुछ अच्छा खोजना पड़ता है। साथ ही मैं कुछ समय से टी20 टीम से बाहर हूं। मुझे पता है कि एक खिलाड़ी के रूप में मैं कहां खड़ा हूं. मुझे पता है कि मुझे वापस आने के लिए क्या करना है। मैं इस आईपीएल सत्र का इंतजार कर रहा हूं। उम्मीद है कि इससे मुझे वह मंच मिलेगा जहां मैं वापस जाकर अपने क्रिकेट का आनंद ले सकूंगा।

वित्तीय प्रबंधन को बेहतर और मजबूत बनाने में काफी मददगार साबित होंगे : अनिल कुमार

- पर्याप्त सहायक दस्तावेज रखने के महत्व पर भी चर्चा की गई
- हमारे प्रशासन ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक है

नई दिल्ली। एजेंसी

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के महासचिव अनिल कुमार ने 6 और 7 नवंबर को श्रीलंका के कोलंबो में हुई फीफा वित्तीय प्रशासन कार्यशाला में भाग लेने को शानदार अनुभव बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन सदस्य संघों के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने और मजबूत बनाने में काफी मददगार साबित होंगे। एआईएफएफ की ओर से बुधवार को जारी बयान में अनिल कुमार ने कहा कि फीफा वित्तीय प्रशासन कार्यशाला में भाग लेना एक अमूल्य अनुभव रहा है। वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सर्वोत्तम प्रथाओं पर साझा की गई अंतर्दृष्टि हमारे प्रशासन ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

वित्तीय प्रशासन मार्गदर्शिका की प्रस्तुति से शुरू हुई कार्यशाला में हितों के टकराव, योजना और बजट तथा खरीद प्रक्रिया जैसे विषयों पर चर्चा, समूह कार्य और केस सत्र शामिल थे, साथ ही पर्याप्त सहायक दस्तावेज रखने के महत्व पर भी चर्चा की गई।

सत्रों में फीफा फॉरवर्ड कार्यक्रम के संदर्भ में जवाबदेही, पारदर्शिता और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया गया। श्रीलंका में आयोजित कार्यशाला में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, ईरान, किर्गिज गणराज्य, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के सदस्य संघों के महासचिवों और वित्त निदेशकों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम नव स्थापित फीफा कैम्पस के बैनर तले आयोजित किया गया, जो सदस्य संघों के लिए फीफा क्षमता विकास और शिक्षा पहलों के लिए केंद्रीय फुटबॉल शिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है।

संक्षिप्त खबरें

इंग्लैंड के खिलाफ शेष तीन टी20 मैचों से बाहर हुए रसेल, अल्जारी जोसेफ की वापसी

बारबाडोस। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के बाकी बचे तीन मैचों से बाहर हो गए हैं। रसेल को बारबाडोस में श्रृंखला के शुरूआती मैच के दौरान टखने में चोट लग गई थी और वह दूसरे मैच से बाहर हो गए थे। यह मैच वेस्टइंडीज सात विकेट से हार गई थी और श्रृंखला में 2-0 से पीछे हो गई है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने रसेल के स्थान पर ऑलराउंडर शमर स्प्रिंगर को टीम में शामिल किया है। साथ ही तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की भी तीन मैचों के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है। दाएं हाथ के इस गेंदबाज को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच के दौरान मैदान पर हुई घटना के कारण दो मैचों का निलंबन मिला था। क्रिकेट वेस्टइंडीज के अनुसार अल्जारी जोसेफ, दो मैचों का निलंबन पूरा करने के बाद शमर जोसेफ की जगह टीम में शामिल होंगे।

अर्जुन तेंदुलकर के पंजे से अरुणाचल 84 पर ढ़ेर

पोरवोरिम। अर्जुन तेंदुलकर (पांच विकेट) और मोहित रेडकर (तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर बुधवार को रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में मुकाबले में गोवा ने अरुणाचल प्रदेश को 84 रनों के स्कोर पर ढ़ेर कर दिया है। आज यहां टॉस जीतकर अरुणाचल प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी अरुणाचल की शरुआत बेहद खराब रही और उसने मात्र 27 के स्कोर पर अपने चार विकेट गवां दिये। नबाम हचांग(शून्य), नीलम ओबी (22), जय भावसार (शून्य), चिन्मय पाटिल (3) रन बनाकर आउट हुये। इन चारों बल्लेबाजों को अर्जुन तेंदुलकर ने आउट किया। इसके अलावा मोजी एटे (एक) रन को भी अर्जुन ने आउट किया। सिद्धार्थ बलोदी (16), संदीप कुमार (12), याब निया (शून्य) पर आउट हुये। कप्तान नबाम अबो ने सर्वाधिक (नाबाद25) रनों की पारी खेली। गोवा के गेंदबाजों ने अरूणाचल प्रदेश की पूरी टीम 30.3 ओवर में 84 के स्कोर पर सिमेट दिया।

स्पोर्ट्स इवेंट में ड्रीम हाउस का रहा दबदबा

लखीमपुर खीरी। एजेंसी

सिटी माण्टेसरी इण्टर कॉलेज में हो रहे इण्टर हाउट स्पोर्ट्स इवेंट 'बिगुल 2.0' 'ए बैटल ऑफ टैलेन्ट' की श्रृंखला में आज चौथे दिन हायर जूनियर व सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों के मध्य ऑक्टोपस रेस, लम्बी कूद, स्लो साइकिल रेस, कबड्डी आदि प्रतियोगिताएं कराई गईं, जिसमें ड्रीम हाउस का दबदबा रहा।

कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम निदेशक नितीश खन्ना, खेल प्रशिक्षक रमेश चन्द्र गुप्ता, पंकज राजवंशी द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के चौथे दिवस हिन्दी माध्यम में सरदार पटेल हाउस विनर रहा व अब्दुल कलाम हाउस रनर रहा। वहीं अंग्रेजी माध्यम में ड्रीम हाउस विनर व विजन हाउस रनर रहा। हिन्दी माध्यम के हायर जूनियर वर्ग में स्लो साइकिल रेस में सरदार पटेल हाउस के कक्षा-9 के छात्र ऋषभ प्रथम व अब्दुल कलाम हाउस के कक्षा-6 के छात्र रंजन कुमार द्वितीय स्थान पर रहे। वहीं सीनियर वर्ग में सरदार पटेल हाउस के कक्षा-12 के छात्र तरुण कश्यप रहे प्रथम व अब्दुल कलाम हाउस के कक्षा-10 के छात्र मो. अनस द्वितीय रहे। वहीं 'लम्बी कूद' में सरदार पटेल हाउस के कक्षा-10 के छात्र जाफेद प्रथम व गुरुगोविन्द हाउस के कक्षा-12 के छात्र अंशुमान वर्मा द्वितीय रहे।

इसी प्रकार अंग्रेजी माध्यम के हायर जूनियर वर्ग में 'स्लो साइकिल रेस' में विजन हाउस के कक्षा-9 के छात्र आदित्य बक्शी रहे प्रथम व वायब्रेन्ट हाउस के कक्षा-9 के छात्र अभिनव सोनी द्वितीय रहे जबकि सीनियर वर्ग में विजन हाउस के कक्षा-11 के छात्र कन्हैया प्रथम व डिवाइन हाउस के कक्षा-10 के छात्र आदित्य शर्मा द्वितीय रहे। वहीं 'लम्बी कूद' में वायब्रेन्ट हाउस के कक्षा-12 के छात्र सार्थक वर्मा ने प्रथम व ड्रीम हाउस के कक्षा-10 के छात्र अनमोल पाण्डेय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

विद्यालय प्रबन्धक विशाल सेठ, संचालिका लेखनी सेठ व प्रधानाचार्य धीरेन्द्र सिंह ने प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन किया। इस दौरान विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम सीनियर इंचार्ज एमबी मिश्रा, प्राइमरी इंचार्ज पारुल श्रीवास्तव, शिक्षक आरके सिंह, उपदेश तिवारी, उत्तम, अभिषेक वर्मा, रवीन्द्र दीक्षित, मुबस्सिर आफताब, विकास, अश्वनी सक्सेना, अंकित, अश्वनी कुमार, अखिलेर्श, अजय दीक्षित, रोशन लाल गौड़, रवि, विद्याधर मिश्र सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे।

बुसानन को हराकर सिंधु जापान मास्टर्स के दूसरे दौर में

कुमामोटो (जापान)। एजेंसी

भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने बुधवार को जापान मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान को हराकर टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बना ली हैं। सिंधु ने खेले गये मुकाबले में अपने स्मैश और ड्रॉप्स का शानदार प्रदर्शन करते हुए थाई प्रतिद्वंद्वी बुसानन को 21-12, 21-8 से शिकस्त दी। दूसरे दौर में भारतीय खिलाड़ी सिंधु का मुकाबला मिशेल ली से होगा। सिंधु की शुरूआत खराब रही और इसका फायदा उठाते हुए बुसानन ने पहले गेम की शुरूआत में 5-1 की बढ़त बना ली।

लेकिन इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए स्कोर 7-7 कर दिया और फिर उसे बढ़ाकर 11-9 कर दिया। सिंधु ने ब्रेक के बाद अपनी बढ़त को 14-10 कर दिया। सिंधु ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए 21-12 से पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में सिंधु ने शानदार शुरूआत की। इस दौरान बुसानन ने वापसी करने के लिए संघर्ष करती हुई देखी गई लेकिन सिंधु ने 4-0 की बढ़त बनाई। इसके बाद सिंधु की कुछ गलतियों का फायदा उठाते हुए बुसानन ने स्कोर 4-5 कर दिया।

चोटिल वु लेई, बहरीन के खिलाफ विश्वकप क्वालीफायर मैच में नहीं खेलेंगे

दुबई। एजेंसी

चीन की फुटबॉल टीम के कप्तान वू लेई को घुटने की चोट के कारण बहरीन के खिलाफ गुरुवार होने वाले फीफा विश्वकप क्वालीफायर मुकाबले नहीं खेलेंगे।

चिकित्सा दल द्वारा अनफिट घोषित किए जाने के बाद वू दुबई में चीन के प्रशिक्षण शिविर से चले गए। चीन के मिडफील्डर वांग शांगयुआन ने कहा वू लेई का चोटिल होकर बाहर होना निश्चित रूप से हमारे लिए अफसोस की बात है। उन्होंने कहा उन्होंने राष्ट्रीय टीम और अपने क्लब के लिए बहुत सारे गोल किए हैं।

वे राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं और उन्होंने मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह सकारात्मक प्रभाव डाला है। चार मैचों के बाद चीन तीन अंकों के साथ ग्रुप सी में सबसे निचले पायदान पर है। वही बहरीन के पांच अंक हैं और वह छह टीमों के समूह में चौथे स्थान पर है।

शाहीन अफरीदी बने नंबर वन एकदिवसीय गेंदबाज

नई दिल्ली। एजेंसी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेदबाज शाहीन शाह अफरीदी फिर दुनिया के नंबर वन एकदिवसीय गेंदबाज बन गए हैं। बुधवार को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष एकदिवसीय गेंदबाज रैंकिंग में अफरीदी ने नंबर वन स्थान हासिल कर लिया है। हाल ही में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के कारण अफरीदी ने 50 ओवर के क्रिकेट में शीर्ष गेंदबाज के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर किया।

उन्होंने तीन मैचों में 12.62 की औसत से आठ विकेट लिए थे। अफरीदी तीन पायदान ऊपर चढ़ गए हैं और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज (दो पायदान नीचे तीसरे स्थान पर) से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, जबकि अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अफरीदी ने इससे पहले पिछले साल भारत में हुए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के दौरान नंबर 1 गेंदबाज की रैंकिंग हासिल की थी। पाकिस्तानी टीम के हारिस राउफ 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि उनके हमवतन नसीम शाह ने भी अपने करियर की नई सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है और 14 स्थान के सुधार के साथ 55वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम एकदिवसीय बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर कामय हैं। दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं। पाकिस्तान टीम के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान दो स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर पहुंचे हैं।

बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो (11 पायदान ऊपर 23वें स्थान पर) और अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई (दो पायदान ऊपर 31वें स्थान पर) भी एकदिवसीय बल्लेबाजों की सूची में आगे बढ़े हैं। अफगानिस्तान के अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नबी एकदिवसीय ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। हालांकि, मेहदी (चौथे स्थान पर) और उमरजई (दो पायदान ऊपर नौवें स्थान पर) ने इस सप्ताह कुछ प्रगति की है।

व्यापार

शेयर बाजार में गिरावट, लगातार 5वें दिन कमजोरी के साथ बंद हुए निफ्टी और सेंसेक्स

नई दिल्ली। एजेंसी

घरेलू शेयर बाजार लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। पूरे दिन के कारोबार में बाजार 1.25 प्रतिशत से भी ज्यादा टूट गया। कारोबार की शुरूआत भी गिरावट के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद पहले 15 मिनट तक खरीदारों ने लिवाली का जोर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मंदड़ियों ने पूरी तरह से बाजार पर अपना कब्जा कर लिया। बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स 1,141 अंक से अधिक और निफ्टी 373 अंक से अधिक टूट गए।

पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 1.25 प्रतिशत और निफ्टी 1.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार में सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। रियल्टी, ऑटोमोबाइल और मेटल सेक्टर में आज सबसे अधिक बिकवाली होती रही। इसी तरह बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल, आईटी, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, हेल्थकेयर, ऑयल एंड गैस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और टेक इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में भी लगातार बिकवाली होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 2.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 3.08 प्रतिशत की कमजोरी के साथ कारोबार का अंत किया।

शेयर बाजार में आई कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में करीब 7 लाख करोड़ रुपये की कमी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 430.36 लाख करोड़ रुपये (अस्थाई) हो गया जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 437.24 लाख करोड़ रुपये था।

लिस्टिंग के बाद स्विगी के शेयरों ने दिखाई मजबूती

नई दिल्ली। एजेंसी

ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के शेयर की शुरूआती चाल ने आईपीओ निवेशकों चेहरे खिला दिए हैं। स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर करीब 7 प्रतिशत प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। आईपीओ के तहत 390 रुपये के भाव पर स्विगी के शेयर जारी किए गए थे। बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 412 रुपये और एनएसई पर इसकी लिस्टिंग 420 रुपये के भाव पर हुई। हालांकिए लिस्टिंग के तुरंत बाद मुनाफा वसूली शुरू हो जाने की वजह से इसके शेयरों में गिरावट आ गई। बिकवाली के कारण स्विगी के शेयर 391 रुपये के स्तर तक गिर गए, लेकिन इसके बाद खरीदारी शुरू होने से इसने तेज छलांग लगा दी। खरीदारी के सपोर्ट से ये शेयर उछल कर 454 रुपये के भाव तक पहुंच गए। लगातार जारी खरीद बिक्री के बीच दोपहर 12 बजे स्विगी के शेयर 54 रुपये की मजबूती के साथ 444 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहे थे। स्विगी का 11,327.43 करोड़ रुपये का ये आईपीओ इस साल घरेलू शेयर बाजार में लॉन्च होने वाला दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ है। अक्टूबर के महीने में हुंडई मोटर ने 27,870 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च करके घरेलू शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया था।

अक्टूबर महीने में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में मामूली वृद्धिः सियाम

नई दिल्ली। त्योहारी मांग की वजह से यात्री वाहनों की थोक बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर मामूली बढ़त के साथ 3,93,238 इकाई रही है। अक्टूबर 2023 में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 3,89,714 इकाई रही थी। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि अक्टूबर महीने में कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़कर 21,64,276 इकाई पर पहुंच गई जबकि अक्टूबर 2023 में ये 18,95,799 इकाई रही थी। स्कूटर की बिक्री अक्टूबर में 22 फीसदी की वृद्धि के साथ 7,21,200 इकाई रही है। इस दौरान मोटरसाइकिल की थोक बिक्री 11 फीसदी की बढ़त के साथ 13,90,696 इकाई हो गई जबकि अक्टूबर 2023 में यह 12,52,835 इकाई रही थी। हालांकि, पिछले महीने अक्टूबर में मोपेड की बिक्री घटकर 52,380 इकाई रह गई जबकि एक वर्ष पूर्व इसी माह में यह 53,162 इकाई रही थी।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत एशिया में मिला जुला कारोबार

नई दिल्ली। एजेंसी

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं एशियाई बाजारों में आज मिला-जुला कारोबार हो रहा है।

अमेरिका में अक्टूबर की महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। आशंका जताई जा रही है कि महंगाई दर के आंकड़ों में तुलनात्मक तौर पर बढ़ोतरी हो सकती है। इसीलिए पिछले सत्र के दौरान अमेरिकी बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव बना रहा। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.29% की कमजोरी के साथ 5,983.76 अंक के स्थान पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 0.09% की गिरावट के साथ 19,281.87 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया।

डाउ जॉन्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.05% फिसल कर 43,889.67 अंक के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान चौतरफा बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसके कारण यहां के तीनों प्रमुख सूचकांक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए।

जोन 10 में जेडीए खसरें की बेशकीमती सरकारी ज़मीन पर 'अशोक विहार नामक अवैध कॉलोनी का लगा घुंण'

कब चेतेंगे संबंधित जिम्मेदार? कब चलेगा पीला पंजा, कब गरजेगा जेडीए का बुलडोजर

ब्लैक लिस्टेड श्रीराम पुरा गृह निर्माण सहकारी समिति सोसाइटी ने मचा रखी हैं ग़दर

चमकता राजस्थान

जयपुर (खलील कुरैशी) राजधानी जयपुर में सरकार इन दिनों प्रदेश के चहुंमुखी विकास और आगामी बहुउद्देशीय योजनाओं से समावेशी कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान की तैयारियों में युद्ध स्तर पर व्यस्त हैं शासन-प्रशासन एवं जेडीए की इस व्यस्तता को भू-माफियाओं द्वारा इसे आपदा में अवसर समझकर इकोलॉजिकल जोन 10 सहित सभी जोनों में नवीन अवैध कॉलोनियों की एक अव्यवस्थित श्रृंखला की झड़ी लगा दी है इसी क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण के इकोलॉजिकल जोन 10 परिक्षेत्र के बगराना ग्राम स्थित नमकीन फैक्ट्री के पास बांके बिहारी मंदिर के आगे जेडीए स्वामित्व के खसरें 339 में बेशकीमती सरकारी जमीन पर अशोक विहार नामक अवैध कॉलोनी बसा दी है इस अवैध कालोनी में ब्लैक लिस्टेड सोसायटी श्रीरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टों की बंदरबांट की गयी है आपकों बता दें कि इकोलॉजिकल क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत बगराना स्थित जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध क़ब्जा-अतिक्रमण कर अवैध बाउंड्रीवाल बनाकर भू-खंड बैचान किये गये है जिससे ना सिर्फ राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का भारी राजस्व का नुक़सान हुआ बल्कि भोले भाले और शरीफ़ आम आदमी की गा-ढ़ी कमाई पर भी भू-माफियाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से डाका डाला है गौरतलब है कि उक्त नवीन अवैध कॉलोनी इकोलॉजिकल जोन क्षेत्राधिकार में बगराना स्थित नमकीन फैक्ट्री के पास में जेडीए स्वामित्व की बेशक़ीमती सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध क़ब्जा-अतिक्रमण कर भूमि को समतल कर अवैध कॉलोनी बसाने के लिए बाउंड्रीवाल बना ली, इसके साथ ही अवैध निर्माण भी कर दिया गया है उन्होंने बताया कि यह जमीन करोड़ों रुपए की है। पर बड़ा सवाल है कि आखिर इस अवैध कालोनी अशोक विहार में आख़रि गरजेगा जेडीए का बुलडोजर

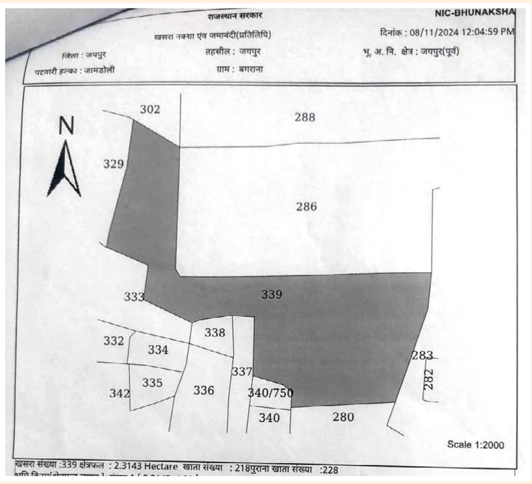

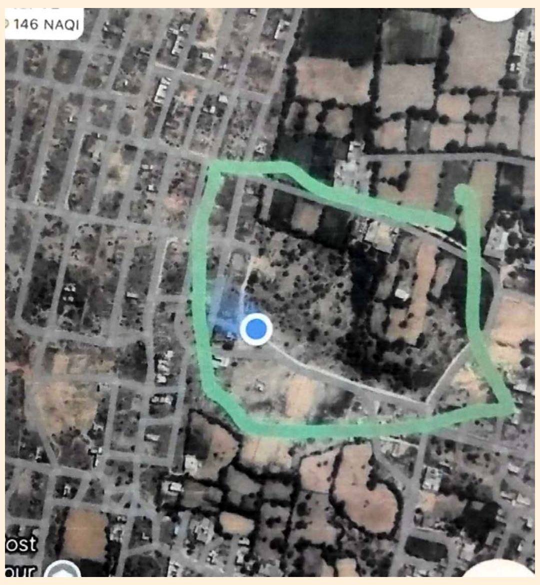

जेडीए प्रशासन के नवीन अवैध कॉलोनियों के संबंध में कार्रवाई को लेकर किये जा रहें जीरों टॉलरेंस निति के दावों पर लगा सवालियां निशान

भू-माफियाओं द्वारा खुलेआम आमजन की गाढ़ी कमाई को लगाया जा रहा है धोखे का चुना

बड़ा सवाल आखिर क्यों नहीं होते हैं ब्लैक लिस्टेड/ फर्जी सोसायटियों के पदाधिकारियों पर मुकदमे

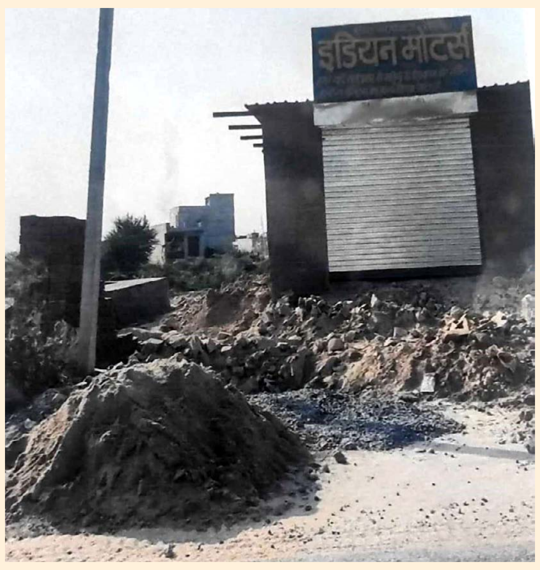

इन नवीन अवैध कॉलोनियों से आमजन का जीना हराम, फिर भी नहीं होती हैं प्रभावी कार्रवाई

जोन-10 में मानबाग,नाई की थड़ी, जयसिंहपुराखोर, सुमेल, बगराना, विजयपुरा, खोरी रोपाडा, खो- नागोरियान, गोनेर रोड़, कानोता रोड़,सांभरीया रोड़, आदि स्थानों पर इकोलॉजिकल परिक्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की बाढ सी आ गयी । जागरूक लोग कई सालों से शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन जेडीए ने कार्रवाई नहीं की। आसपास के गांवों व कॉलोनियों के लोग प्रदूषण से परेशान हैं। इनके खिलाफ जेडीए, जिला प्रशासन व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में लंबी लड़ाई लड रहे हैं जेडीए जोन -10 में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों से आमजन का जीवन जीना दूभर हो गया है।

जेडीए को करनी होगी इन अवैध कॉलोनियों पर बड़ी एवं प्रभावी कार्रवाई

कानूनी विशेषज्ञों ने बताया जयपुर विकास प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों के जिम्मेदारों को भू-माफियाओं द्वारा अनाधिकृत एवं अवैध तरीके से जेडीए की सरकारी एवं गैर-सरकारी जमीनों सिवायचक भूमि मैदानों नालों, ख़ाली पड़ी जमीनों आदि पर अवैध तरीके से बसायीं जा रही इन कालोनियों के खिलाफ पुख्ता न्यायसंगत कार्रवाई किया जाना अतिआवश्यक है इसके अलावा संबंधित विभाग को इन अवैध कालोनियों की जानकारी देनी होगी। ये जानकारी सरकार को अनाधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास की बेहतर योजना बनाने में मदद करनी होगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पानी दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा काम किया जाएगा।

ब्लैक लिस्टेड श्रीराम पुरा गृह निर्माण सहकारी समिति सोसाइटी ने मचा रखी हैं ग़दर

ग्राम बगराना में नमकीन फैक्ट्री के पास बांके बिहारी मंदिर के आगे सृजित अवैध कॉलोनी अशोक विहार में ब्लैक लिस्टेड सोसायटी श्री रामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति ने गंद मचा रखी हैं बिना खौफ के ,बैकडेट में पट्टे वितरित कर अशोक विहार को बसाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसी तरह से शहर के बाहरी जोन में धड़ल्ले से बैकडेट में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है। जेडीए ने पिछले चार महीने में एक दर्जन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ तोडफ़ोड़ की कार्रवाई की है। तोड़फोड़ के बाद जेडीए ने यहां पट्टे देने वाले लोगों व सोसायटियों के खिलाफ जांच ही नहीं की। ऐसे में एक भी सोसायटी व बैकडेट में पट्टा देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो पाई है। आपकों बता दें कि जोन 10, 12,13 व 14 सहित अन्य के इलाकों में सरकारी एवं निजी जमीनों पर बैकडेट में सोसायटी पट्टों में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है। जेडीए ने पिछले चार महीने में एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन कुछ सिफारिशी अवैध कॉलोनियों पर जोन से मौका व रेवन्यू रिकॉर्ड की रिपोर्ट नहीं आने के नाम पर कार्रवाई रोककर लिपापोती हुई है। वहीं रिपोर्ट आने में लगे एक साल के कारण प्रवर्तन अधिकारियों ने कुछ कॉलोनियों को पुरानी बताते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई से ही इंकार

संक्षिप्त समाचार

पाली में बी.एस.टी.सी.कॉलेज का प्रबन्ध संचालक एवं व्याख्याता 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

चमकता राजस्थान। जयपुर !(खलील कुरैशी) 13 नवम्बर, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की पाली-द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये गणेश रावल प्रबन्ध संचालक एवं विजय व्याख्याता उज्ज्वल विक्रम बी.एस.टी.सी. कॉलेज, बोमादड़ा रोड़, पाली को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली-द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि उसकी उपस्थिति पूरी करने एवं नम्बर दिलवाने की एवज में गणेश रावल प्रबन्ध संचालक एवं विजय व्याख्याता द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।जिस पर एसीबी जयपुर-द्वितीय के उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की पाली-द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींवसिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी गणेश रावल प्रबन्ध संचालक एवं विजय व्याख्याता को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही

- राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाने की सकारात्मक पहल
- अनाधिकृत नियम विरूद्ध लगाये गये एरियल केबल को हटाने की हुई कार्यवाही

चमकता राजस्थान

जयपुर!(खलील कुरैशी) 13 नवम्बर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देश पर बुधवार को नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा अनाधिकृत एवं नियम विरूद्ध लगाई गई एरियल केबल एवं अनाधिकृत स्वःनिर्मित पोल्स को हटवाने संबंधी कार्यवाही की गईराइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के आयोजन के दृष्टिगत शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाने के लिये नगर निगम ग्रेटर लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के तहत बुधवार को सुबह 10 बजे से ही लक्ष्मी मंदिर तिराहे से नगर निगम ग्रे-टर की टीमों द्वारा कार्यवाही शुरू की गई। मालवीय नगर जोन, जगतपुरा जोन, सांगानेर जोन में यह कार्यवाही उपायुक्त राजस्व प्रथम, लाईन्सेस, होर्डिग शाखा, गैराज शाखा, विद्युत शाखा एवं सतर्कता शाखा द्वारा संयुक्त रूप से की गई। गुरूवार को भी यह कारवाई जारी रहेगी।कार्यवाही के तहत भारत सेतु फ्लाईओवर से सहकार मार्ग, सहकार मार्ग से टोंक रोड़, केन्द्रीय विद्यालय-1 वाया अभिमन्यू मार्ग, जेएलएन मार्ग से जवाहर सर्किल, जवाहर सर्किल से टर्मिनल-1, टर्मिनल 2 से तारों की कूट, तारों की कूट से सांगानेर फ्लाईओवर व अन्य मुख्य मार्गों पर सम्पूर्ण क्रॉसिंग/ अनाधिकृत/नियम विरूद्ध एरियल केबल हटाई गई साथ ही अनाधिकृत पोल्स को भी हटाया गया।आयुक्त ने बताया कि निगम द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार की जा रही है किन्तु अनाधिकृत नियम विरूद्ध एरियल केबल हटाने संबंधी कार्यवाही के तुरन्त बाद ही विभिन्न टेलीकॉम सेवा प्रदाता कम्पनी एवं अन्य डिजिटल केबल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कार्यवाही स्थलों पर स्थित निगम के विद्युत पोल्स पर अवैध रूप से पुनः एरियल केबल को बिछा दिया जाता है। इसलिए ऐसे स्थलों पर विजिलेंस टीम के होमगार्ड द्वारा गश्ती की जायेगी। जिससे कार्यवाही पश्चात उक्त मार्गो पर किसी भी विभिन्न टेलीकॉम सेवा प्रदाता कम्पनी एवं अन्य डिजिटल केबल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अवैध रूप से एरियल केबल ना बिछाई जा सके।उन्होंने बताया कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा बिना अनुमति के लगाये जाने वाली एरियल केबल को हटाने की कार्यवाही के साथ ही संबंधित सेवा प्रदाता कम्पनी के विरूद्ध विधिक कारवाई की जाती रहेगी।

बाल भिक्षावृति उन्मूलन के लिए अभियान उमंग अभियान- 4 प्रारंभ, स्क्रीनिंग करेगी पुलिस

- बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा दे- एडीएम ओम प्रकाश सहारण

चमकता राजस्थान। कोटपूतली-बहरोड़(धर्मेंद्र बंसल) 13 नवंबर। जिले में भिक्षावृति पर रोक लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, श्रम विभाग, बाल सरंक्षण समिति, चाइल्ड लाइन तथा पुलिस विभाग की ओर से संयुक्त रूप से उमंग अभियान- 4 प्रारंभ किया गया है। बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण की अध्यक्षता में उमंग अभियान को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित हुई बैठक में बस स्टैंड तथा शहर के मुख्य चौराहे पर बच्चो का भीख मांगना बंद करने के लिए 30 दिन तक उमंग अभियान-4 चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलाया जाएगा। जिसमें भीख मांगते पकड़े गये बच्चो को उनके सरंक्षण और पुनर्वास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल कल्याण समिति के पास पेश किया जायेगा। बाल भिक्षावृति को रोकने के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान मे प्रत्येक थाने से पुलिस अधिकारियो/ पुलिसकर्मियो की टीम गठित की गई है।बैठक के दौरान पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र बुरड़क, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक सतपाल यादव, समाज कल्याण विभाग के विभाग के गजराज यादव, श्रम विभाग के निरीक्षक अरविंद दीक्षित मौजूद रहे।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अभय सिंह चौहान के लिए एम बी प्रिंटर्स, सी 74 सुदर्शन पूरा, जयपुर से मुद्रित एवं 1ए देवी नगर विस्तार, देवी नगर गली नं. 6 जयपुर 302019 से प्रकाशित। सम्पादक : अभय सिंह चौहान,
मोबाइल : 9314505000 (पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार) संपादक : खलील कुरैशी, मोबाइल : 7891542929